



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08012021-224297
CG-DL-E-08012021-224297

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8]
No. 8]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 8, 2021/ पौष 18, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 8, 2021/PAUSHA 18, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2021

मामला सं. (एसएसआर 05/2020)

विषय : चीन जन. गण., मलेशिया, थाइलैंड और श्रीलंका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "6 एमएम अथवा उससे अधिक मोटाई वाले प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड" के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 7/6/2020-डीजीटीआर.—यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे बाद में "अधिनियम" कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां "नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

- निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे यहां "प्राधिकारी" भी कहा गया है) ने चीन जन. गण., मलेशिया, थाइलैंड और श्रीलंका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 6 एमएम अथवा उससे अधिक मोटाई वाले प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड (जिसे आगे यहां "संबद्ध सामान" अथवा "पीयूसी" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में 06 जून, 2008 को पाटनरोधी जांच शुरू की गई थी और दिनांक 02 फरवरी, 2009 की प्राथमिक जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 14/12/2007 द्वारा प्राथमिक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई

थी। प्राथमिक जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा 27 फरवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या 21/2009-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। उसके बाद, प्राधिकारी ने 26 अगस्त, 2009 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 14/12/2007-डीजीएडी द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हुए अंतिम जांच परिणाम जारी किए। अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने दिनांक 08 अक्तूबर, 2009 की अधिसूचना संख्या 116/2009-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया। उसके बाद संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में प्राधिकारी द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या 15/28/2013-डीजीएडी द्वारा निर्णायक समीक्षा (एसएसआर) जांच शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने दिनांक 17 अगस्त, 2015 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 15/28/2013-डीजीएडी द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से पाटन जारी रहेगा अथवा बार-बार होगा और परिणामस्वरूप क्षति होगी तथा पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश की अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने दिनांक 21 अक्तूबर, 2015 की अधिसूचना संख्या 48/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा शुल्क लगाए।

2. अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि पहले न हटाया गया हो, उसे लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर प्रभावी होना बंद हो जाएगा और प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे यह समीक्षा करें कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है। उपर्युक्त के अनुसार, प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए विधिवत सिद्ध अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करें कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।

3. नियमावली के नियम 23(1ख) में निम्नलिखित प्रावधान है:

"..... अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क उसके लगाए जाने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा बशर्ते निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त अवधि से पूर्व अपनी खुद की पहल पर या घरेलू उद्योग की ओर से किए गए विधिवत पुष्टिकृत अनुरोध के आधार पर उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उचित अवधि के भीतर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उक्त शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।"

4. मैसर्स ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड/ग्रीनपैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेंचुरी प्लाईवर्क (इंडिया) लि. और रूसिल डेकर लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" कहा गया है) ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों का पाटन जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने का आरोप लगाते हुए अधिनियम तथा नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष घरेलू उद्योग की ओर से विधिवत सिद्ध आवेदन पत्र दायर किया और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसे जारी रखने के लिए अनुरोध किया है।
5. पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, घरेलू उद्योग की ओर से दायर पाटन एवं क्षति की संभावना के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के साथ सिद्ध आवेदन पत्र के आधार पर, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क निरंतर लगाया जाना जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने और यह जांच करने के लिए कि क्या उपर्युक्त शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है, 28 फरवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या फा. सं. 7/6/2020-डीजीटीआर (एसएसआर संख्या 5/2020) द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की।
6. सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के अनुसरण में, केंद्र सरकार ने दिनांक 13 अक्तूबर, 2020 की अधिसूचना संख्या 30/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा पाटनरोधी शुल्क 20 जनवरी, 2021 तक बढ़ा दिए।

7. वर्तमान समीक्षा के क्षेत्र में संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में पूर्व जांचों के सभी पहलू शामिल हैं।

ख. प्रक्रिया

8. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:
- (i) प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने से पूर्व वर्तमान आवेदन पत्र प्राप्त होने के संबंध में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।
 - (ii) प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित 28 फरवरी, 2020 की अधिसूचना जारी की।
 - (iii) प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग तथा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार अन्य घरेलू उत्पादकों को जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार दें।
 - (iv) प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को तथा ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों को आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई।
 - (v) भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने-अपने देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रति भी उन्हें संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पतों सहित भेजी गई थी।
 - (vi) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, संगत सूचना मंगाने के लिए संबद्ध देशों में निम्नलिखित उन ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजीं जिनके ब्यौरे आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए थे:
 - क. मेरबोक एमडीएफ लंका प्रा. सीमित
 - ख. डोंगवा फाइब्रेबोर्ड एसडीएन. बीएचडी.
 - ग. दैकेन सरावक बीडीएच. एसडी.
 - घ. मैसर्स एवरग्रीन फाइबर बरहाड (जेबी) एसडीएन. बीएचडी.
 - ङ. मैसर्स एवरग्रीन फाइबर बरहाड (ईएफबी)
 - च. रॉबिन रिसोर्सेज (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी.
 - छ. मैसर्स सीगमट पैनल बोर्ड्स एसडीएन. बीएचडी.
 - ज. मैसर्स एडवांस फाइबर कं
 - झ. खोकेन एमडीएफ बोर्ड
 - ञ. वानाचर्ड पैनल इंडस्ट्रीज कं. लिमिटेड
 - ट. सियाम फाइबरबोर्ड कंपनी लिमिटेड
 - ठ. मैसर्स मेट्रो फाइबर कं लिमिटेड
 - ड. मैसर्स वानाचर्ड ग्रुप पब्लिक कंपनी लिमिटेड
 - ढ. मैसर्स मेट्रो एम.डी.एफ. कंपनी लिमिटेड

- ण. टॉमरिक इंटरनेशनल ट्रेडिंग लिमिटेड
 त. नानजिंग ईटीआई ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
 थ. लिनी बैदेली इंटरनेशनल ट्रेड कं. लिमिटेड
 द. लिनी होंगफु टिम्बर कंपनी लिमिटेड
 ध. वानझोऊ टिम्बर ग्रुप कं लिमिटेड
 न. शोगुआंग गुईहे इकोनॉमिक एंड ट्रेड कंपनी लिमिटेड
 प. झांजियांग किंगसटर बिल्डिंग मैटेरियल कं. लिमिटेड
 फ. गुआंगडोंग वीहुआ होलिंग कं, लिमिटेड
 ब. लिनी बैदेली इंटरनेशनल ट्रेड कं. लिमिटेड
 भ. शुनलोंग एमडीएफ- बोर्ड कंपनी लिमिटेड
 म. शंघाई सिंधो पैनल कंपनी लिमिटेड
 य. शुयांग न्यू कॉन्सेप्ट वुड कं. लिमिटेड
- (vii) संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्धारित तरीके से प्रश्नावली के उत्तर दायर किए:
 क. पैनल एमडीएफ कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
 ख. राबिन रिसोर्सेस (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी., मलेशिया
- (viii) प्राधिकारी ने एडवांस फाइबर एंड वाइजवुड्स द्वारा दायर निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर रद्द किए हैं क्योंकि वे निर्धारित तरीके से दायर नहीं किए गए थे।
- (ix) प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध सामानों उन निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता एसोसिएशनों को जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजी जिनके नाम और पते प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए थे और उन्हें सलाह दी कि वे नियम 6(4) के अनुसार प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत लिखित में अपने ज्ञात विचार दें:
 क. कृष्णा प्लाईवुड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
 ख. जैकन्स वीनर्स एंड पैनल्स प्राइवेट लिमिटेड
 ग. लेबल सेल्स कारपोरेशन
 घ. कलिंग इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
 ङ. श्रीवरी ट्रेडर्स
 च. विकट्री प्लाईवुड डिस्ट्रीब्यूटर्स
 छ. थमारापल्ली ब्रदर्स ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
 ज. मैथ्यूसन्स इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
 झ. आर. जे. मेटल्स
 ञ. फेरोक बोर्डर्स लिमिटेड
- (x) तथापि, किसी भी आयातक/प्रयोक्ता/प्रयोक्ता एसोसिएशन ने वर्तमान जांच में कोई अनुरोध अथवा प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं किए हैं।
- (xi) निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने जांच की शुरुआत की अधिसूचना के उत्तर में प्रतिभागिता के पत्र और/अथवा कानूनी अनुरोध दायर किए हैं:
 क. मैट्रो एमडीएफ कं. लि., थाईलैंड
 ख. वाइसवुड्स कं. लि., थाईलैंड

ग. एस.पी.बी. पैनेल इंडस्ट्रीज कं. लि., थाईलैंड

घ. थाई पैनेल प्रोडक्ट इंडस्ट्री क्लब (टीपीपीआईसी)

- (xii) जिन निर्यातकों, विदेशी उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिए हैं अथवा इस जांच से संगत सूचना नहीं दी है, उन्हें असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना गया है।
- (xiii) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी आवश्यक था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।
- (xiv) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले में रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। जब कभी उन्होंने सार्वजनिक फाइल के निरीक्षण और उनसे दस्तावेजों की प्रतियों के लिए अनुरोध किया, तो उन्हें उपलब्ध कराई गई थी।
- (xv) वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2018 से 30 सितंबर, 2019 की गई है। क्षति जांच अवधि 1 अप्रैल, 2015 – 31 मार्च, 2016, 1 अप्रैल, 2016 – 31 मार्च, 2017, 1 अप्रैल, 2017 – 31 मार्च, 2018 तथा जांच की अवधि मानी गई है।
- (xvi) आवेदकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यक समझी गई सीमा तक अतिरिक्त/पूरक सूचना मांगी गई थी। घरेलू उद्योग तथा निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा दिए गए आंकड़ों का सत्यापन इस जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था।
- (xvii) क्षति रहित कीमत (एनआईपी) सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-3 के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और निर्माण तथा बिक्री लागत के आधार पर है। यह इस बात को सुनिश्चित करने के लिए निकाली गई है कि क्या पाटन मार्जिन से कम शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- (xviii) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से पिछले तीन वर्षों के लिए लेन-देन वार आंकड़ों के संबंध में प्राप्त सूचना और जांच की अवधि भारत में संबंधित उत्पाद की मात्रा और आयातों का मूल्य निर्धारित करने के लिए अपनाई गई है।
- (xix) नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 11 नवंबर, 2020 को आयोजित सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को अवसर भी प्रदान किया। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में भाग लिया, उन सभी को लिखित अनुरोध दायर करने और उसके बाद यदि कोई प्रत्युत्तर है, तो उन्हें दायर करने का अवसर प्रदान किया गया था।
- (xx) इस जांच प्रक्रिया के दौरान, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को जहां भी संगत पाए गए, प्राधिकारी द्वारा इन अंतिम जांच परिणामों में हल किया गया है।
- (xxi) जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने सूचना देने से इंकार किया है अथवा अन्यथा वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना नहीं दी है अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अंतिम जांच परिणाम रिकार्ड किये हैं।
- (xxii) नियमावली के नियम 16 के अनुसार, जांच के अनिवार्य तथ्य 28 दिसंबर, 2020 के प्रकटन विवरण द्वारा ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किए गए थे और उन पर प्राप्त टिप्पणियां, जिन्हें प्राधिकारी द्वारा संगत माना गया था, इन जांच परिणामों में हल कर दी गई हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध

पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकतर प्रकटन पश्चात अनुरोध उनके पूर्व अनुरोधों की मात्र पुनरावृत्ति हैं। तथापि, प्रकटन पश्चात अनुरोधों की संगत समझी गई सीमा तक इन अंतिम जांच परिणामों में जांच की जा रही है।

- (xxiii) इन अंतिम जांच परिणामों में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई तथा नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- (xxiv) संबद्ध जांच के लिए जांच की अवधि के दौरान प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 70.79 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु

9. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए विचाराधीन उत्पाद प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड है जो प्लेन एमडीएफ बोर्ड के रूप में भी जाना जाता है।
10. यह ताप और दबाव लगाकर यूरिया फॉर्मेलिडहाइड रेसिन अथवा मेलामाइन के साथ चिपका हुआ वुड वेस्ट फाइबर से बनाया गया सम्मिश्रित वुड उत्पाद है। इसका प्रयोग व्यापक रूप से उसकी मुलायम और एक रूप फिनिश के कारण पार्टिशन, मॉड्यूलर फर्नीचर, कैबिनेट आदि के लिए किया जाता है। एमडीएफ बोर्ड का उत्पादन प्लेन फॉर्म में किया जाता है और लेमिनेशन एक अतिरिक्त प्रसंस्करण है जो प्लेन एमडीएफ बोर्ड के उत्पादन के बाद किया जाता है।
11. लेमिनेटिड मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड (लेमिनेटिड एमडीएफ बोर्ड) विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर है। 6 एमएम की मोटाई से कम वाले प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड को उत्पाद क्षेत्र से अलग किया गया है।
12. तदनुसार, विचाराधीन उत्पाद "6 एमएम अथवा उससे अधिक मोटाई वाला प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड है और सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 4, सीमा शुल्क उप शीर्ष संख्या 44111300 और 44111400 के तहत वर्गीकृत है।" तथापि, संबद्ध सामानों का आयात अन्य प्रशुल्क उप शीर्ष अर्थात् 44111200, 44111292, 44111293 और 44111294 के तहत भी किया जा रहा है।

ग.1 घरेलू उद्योग के विचार

13. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- (i) वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, अतः विचाराधीन उत्पाद वही रहता है जो मूल तथा पूर्व की गई जांचों में परिभाषित है। इसके अतिरिक्त, इस अवधि में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई है। अतः घरेलू उद्योग विचाराधीन और समान उत्पाद के संबंध में पूर्व की जांचों का संदर्भ देता है और उन पर विश्वास करता है। घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु का उत्पादन कर रहा है।
- (ii) जहां तक पीसीएन के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्क का संबंध है, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि इस मुद्दे को कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने पूर्व जांच में भी उठाया था, परंतु प्राधिकारी ने उसे स्वीकार नहीं किया था। तथापि, यदि प्राधिकारी निर्णय लेते हैं तो घरेलू उद्योग संगत सूचना उपलब्ध कराएगा।

ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

14. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- (i) रॉबिन विचाराधीन उत्पाद में शामिल तीन प्रकार के बोर्ड उत्पादों अर्थात् ई-0, ई-1/कार्ब और फॉर्मेलिडहाइड एमिशन आधारित ई-2 का विनिर्माण और बिक्री करता है तथा इन ग्रेडों की लागत और कीमत में काफी अंतर है, जैसा कि दी गई लागत संबंधी तालिकाओं से सिद्ध है। विभिन्न ग्रेड भिन्न गोंद तथा इन ग्रेडों पर लागू मानकों के आधार पर अन्य सामग्री का प्रयोग करते हैं जिसके परिणामस्वरूप इन ग्रेडों की लागत और कीमत दोनों में काफी अंतर आ जाता है। विचाराधीन उत्पाद में काफी लागत और कीमत संबंधी अंतरों के साथ परस्पर ग्रेड शामिल हैं जिससे इन विभिन्न ग्रेडों के लिए पाटन और क्षति मार्जिन अलग-अलग निर्धारित करना आवश्यक हो जाता है और इसीलिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन ग्रेड-वार निर्धारित किया जाना चाहिए।

- (ii) उत्तर में पीसीएन के लिए औचित्य दिया गया है कि अभिज्ञात पीसीएन की लागत इन विशिष्ट ग्रेडों में प्रयुक्त इनपुट की लागत में अंतरों के कारण काफी भिन्न होती है।
- (iii) रॉबिन रिसोर्सेस का पीसीएन-वार विश्लेषण का अनुरोध डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.4, जिसमें निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के बीच उचित तुलना अधिदेशित है और डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.6, जिसमें यह उल्लेख है कि पाटित आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन समान वस्तु के घरेलू उत्पादन के संबंध में उस समय किया जाना है जब उपलब्ध आंकड़े अलग पहचान की अनुमति दें, के मद्देनजर औचित्यपूर्ण है।
- (iv) प्राधिकारी को क्षति मार्जिन के निर्धारित के लिए याचिकाकर्ताओं से तदनुसूची क्षति संबंधी आंकड़ों और एनआईपी की मांग करनी चाहिए।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

15. पूर्व तथा वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद 6 एमएम अथवा उससे अधिक मोटाई वाला प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड है। पूर्व की जांच में विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित रूप में परिभाषित था:

"विचाराधीन उत्पाद प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड जो एमडीएफ बोर्ड के रूप में भी जाना जाता है। यह ताप और दबाव लगाकर यूरिया फॉर्मेलिहाइड रेसिन अथवा मेलामाइन रेसिन के साथ चिपका हुआ वुड वेस्ट फाइबर से बनाया गया सम्मिश्रित वुड उत्पाद है। इसका प्रयोग व्यापक रूप से उसकी मुलायम और एक रूप फिनिश के कारण पार्टिशन, मॉड्यूलर फर्नीचर, कैबिनेट आदि के लिए किया जाता है। एमडीएफ बोर्ड का उत्पादन प्लेन फॉर्म में किया जाता है और लेमिनेशन एक अतिरिक्त प्रसंस्करण है जो प्लेन एमडीएफ बोर्ड के उत्पादन के बाद किया जाता है।"

लेमिनेटिड मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड (लेमिनेटिड एमडीएफ बोर्ड) विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर है। 6 एमएम की मोटाई से कम वाले प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड को उत्पाद क्षेत्र से अलग किया गया है। तदनुसार, विचाराधीन उत्पाद 6 एमएम अथवा उससे अधिक मोटाई वाला प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड है।"

16. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामान भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का उपयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से कर रहे हैं। उपर्युक्त के मद्देनजर, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु माना जाता है।
17. जहां तक वर्तमान जांच में पीसीएन अपनाने के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी द्वारा इसी उत्पाद के लिए पाटनरोधी जांच के मामले में इस मुद्दे को पूर्व में लिया गया था, जिसमें इस आधार पर पीसीएन सिद्धांत को न अपनाने का निर्णय लिया गया था। प्राधिकारी द्वारा पूर्व में लिए गए कदम से विचलित होने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता।
18. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, अतः विचाराधीन उत्पाद वही रहता है जो पूर्व की गई जांच में है। संबद्ध सामान शुल्क उप शीर्ष संख्या 44111300 और 44111400 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के तहत वर्गीकरणीय है। तथापि, संबद्ध सामानों का आयात अन्य प्रशुल्क उप शीर्षों अर्थात् 44111200, 44111292, 44111293 और 44111294 के तहत भी किया जा रहा है। यह सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह इस जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं हैं।

घ. घरेलू उद्योग और आधार

19. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:

"(ख) 'घरेलू उद्योग' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के

कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

घ.1 घरेलू उद्योग के विचार

20. घरेलू उद्योग के क्षेत्र एवं आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- (i) निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत के लिए आवेदन पत्र ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड/ग्रीनपैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेंच्युरी प्लाईबोर्ड (इंडिया) लि. और रूसिल डेकर लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से दायर किया गया है। करार की संयुक्त योजना के तहत ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड को ग्रीनपैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड से विलयविहीन कर दिया गया था। ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड/ ग्रीनपैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेंच्युरी प्लाईबोर्ड (इंडिया) लि. और रूसिल डेकर लिमिटेड ने वर्तमान जांच के संबंध में सभी संगत सूचनाएं उपलब्ध कराई हैं।
- (ii) ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड/ग्रीनपैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेंच्युरी प्लाईबोर्ड (इंडिया) लि. और रूसिल डेकर लिमिटेड ने संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है।
- (iii) ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड/ग्रीनपैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेंच्युरी प्लाईबोर्ड (इंडिया) लि. और रूसिल डेकर लिमिटेड प्रत्यक्ष रूप से अथवा परोक्ष रूप से संबद्ध देशों में किसी आयातक अथवा नियम 2(ख) के अभिप्राय से पाटित वस्तु के किसी आयातक से संबद्ध नहीं हैं।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

21. घरेलू उद्योग के क्षेत्र एवं आधार के संबंध में निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- (i) यह स्पष्ट नहीं है कि क्या याचिकाकर्ताओं का आधार है क्योंकि सामान्य रूप में घरेलू उद्योग की तुलना में याचिकाकर्ताओं के उत्पादन के लिए अनुबंध-2.2 में कोई प्रतिशतता नहीं दी गई है।
- (ii) विचाराधीन सामान के 6 अन्य भारतीय उत्पादक हैं जो वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षकारों के रूप में सहयोग नहीं कर रहे हैं।
- (iii) यह संदेहास्पद है कि क्या ये तीन आवेदक अकेले "घरेलू उद्योग" हैं। यह तथ्य कि अन्य 6 भारतीय उत्पादक इस जांच में शामिल नहीं होना चाहते, क्षति विश्लेषण की वैधता को कम करते हैं।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

22. वर्तमान मामले में आवेदन पत्र ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड/ग्रीनपैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेंच्युरी प्लाईबोर्ड (इंडिया) लि. और रूसिल डेकर लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे आवेदक कंपनी भी कहा गया है) द्वारा संयुक्त रूप से दायर किया गया है, जिनका कुल भारतीय उत्पादन में 47 प्रतिशत हिस्सा है। इन आवेदक कंपनियों ने निर्धारित प्रपत्र के अनुसार संगत सूचना दी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के भारत में 6 अन्य विनिर्माता अर्थात् मैसर्स बालाजी एक्शन बिल्डवेल, मैसर्स शिरडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैसर्स मंगलम टिम्बर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, मैसर्स पायनियर पैनल प्रोडक्ट्स, मैसर्स मेट्रो पैनल्स इंडस्ट्रीज और मैसर्स रंगा पार्टिकल बोर्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैं। तथापि, इन उत्पादकों ने वर्तमान जांच का न तो समर्थन किया है और न ही विरोध।
23. आवेदक कंपनियों ने जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। न ही वे संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के किसी उत्पादक/निर्यातक से संबद्ध हैं और न ही भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबद्ध हैं।
24. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करते हुए, प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक कंपनियों अर्थात् ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड/ग्रीनपैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेंच्युरी प्लाईबोर्ड (इंडिया) लि. और रूसिल डेकर लिमिटेड के उत्पादन का समान वस्तु के घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात है और इस प्रकार आवेदक नियमावली के नियम

2(ख) के अभिप्राय के अंतर्गत पात्र घरेलू उद्योग हैं। अतः आवेदन पत्र नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

ड.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

25. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- (i) निर्यातकों और उत्पादकों ने अत्यधिक गोपनीयता का सहारा लिया है। दायर उत्तरों का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय दावा की गई सूचना की सार्थक समझ नहीं देते।
- (ii) उत्तरदाता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय रखी गई सूचना निर्यातक प्रश्नावली के उत्तरों का अनिवार्य भाग है। अगोपनीय रूपांतर में इतनी महत्वपूर्ण सूचना के अभाव के कारण घरेलू उद्योग कोई सार्थक अनुरोध करने और उत्तरों में विसंगतियों अथवा गलत प्रस्तुतियों की पहचान करने में प्राधिकारी की सहायता करने में असमर्थ है।
- (iii) निर्यातकों ने परिशिष्टों का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर नहीं दिया है। यहां तक कि सूचीबद्ध सूचना घरेलू उद्योग को उपलब्ध नहीं कराई गई है।
- (iv) निर्यातकों ने वह सूचना नहीं दी है जो सार्वजनिक पटल पर मुक्त रूप से उपलब्ध है।
- (v) निर्यातकों, एडवांस फाइबर एंड वाइजवुड्स द्वारा दायर अनुरोध पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के उल्लंघन में हैं। उत्तरों के अगोपनीय रूपांतर में केवल लेख हैं और कोई परिशिष्ट नहीं हैं। अर्जेंटीना-सेरिमिक टाइल्स के मामले पर विश्वास किया गया है जिसमें पैनल ने माना है कि प्राधिकारी केवल तभी निर्धारण करने के लिए गोपनीय सूचना पर विश्वास कर सकते हैं, यदि अगोपनीय रूपांतर हितबद्ध पक्षकारों को सूचित करें और उन्हें उनके हितों की रक्षा करने में समर्थ बनाएं। घरेलू उद्योग ने इस संबंध में एस.आर. स्टील लिमिटेड बनाम भारत संघ और एच.आर. जॉनसन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में सेसटेट के निर्णयों पर भी विश्वास किया था जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि अगोपनीय सार प्रस्तुत किया जाना होता है और यदि सूचना सार के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है तो कारणों का विवरण दिया जाना होता है।
- (vi) पारदर्शिता के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी का यह दायित्व है कि वे पक्षकारों से अगोपनीय सार देने के लिए कहें जो विश्वास के साथ प्रस्तुत सूचना का सार उपयुक्त रूप से समझने दे और यह पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) में शामिल महत्वपूर्ण घटक है।
- (vii) निर्यातकों द्वारा दायर उत्तरों के अगोपनीय रूपांतर गोपनीय सूचना की प्रतिकृति नहीं है। यह प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई परिपाटी और प्रक्रिया तथा 25 मार्च, 2009 की व्यापार सूचना 1/2009, 28 फरवरी, 2020 की व्यापार सूचना 1/2013 के उल्लंघन में है।
- (viii) निर्दिष्ट प्राधिकारी का यह मत है कि गोपनीयता जरूरी नहीं है अथवा यदि सूचना देने वाला सूचना को सार्वजनिक करने का इच्छुक नहीं है या सामान्यीकृत रूप में उसको प्रकट करने का प्राधिकार देने का इच्छुक नहीं है तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की अनदेखी करना चुन सकता सकते हैं और तदनुसार जांच परिणाम जारी कर सकता हैं।
- (ix) घरेलू उद्योग को कोई प्रश्नावली जारी नहीं की गई है। घरेलू उद्योग ने आवेदन पत्र का विस्तृत अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया है। जांच की शुरुआत की अधिसूचना का पैरा 1 और पैरा 8 यह सिद्ध करते हैं कि घरेलू उद्योग सहयोगी है।

ड.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

26. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- (i) अगोपनीय फाइलों में घरेलू उद्योग की अगोपनीय प्रश्नावलियों की प्रति शामिल नहीं है जो सामान्यतः सभी हितबद्ध पक्षकारों को उनके हितों की रक्षा में उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

- (ii) घरेलू उद्योग से संबंधित प्रश्नावली के उत्तर के अगोपनीय सार न होने से थार्ड उत्पादकों को इन कार्रवाईयों में अपने रक्षा के अधिकार पर्याप्त रूप से कार्यान्वित करने में बाधा आई है और यह डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.4 और 6.5 का उल्लंघन है।
- (iii) जांचकर्ता प्राधिकारी ने कोई अतिरिक्त सूचना नहीं मांगी है और कोई कमी वाला पत्र जारी नहीं किया है।
- (iv) घरेलू उद्योग का यह गलत निष्कर्ष है कि उत्तरदाताओं ने सूचना छिपाई है और अत्यधिक गोपनीयता अपनाई है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

27. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:

गोपनीय सूचना : (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।

- 28. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर से युक्त सार्वजनिक फाइल के माध्यम से निरीक्षण के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी जिसमें उन सबसे यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर ई-मेल करें क्योंकि सार्वजनिक फाइल चल रही वैश्विक महामारी के कारण भौतिक रूप से पहुँच से परे थी।
- 29. जहां तक घरेलू उद्योग के प्रश्नावली के उत्तरों का अगोपनीय रूपांतर प्रस्तुत करने का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को कोई प्रश्नावली जारी नहीं की गई है। घरेलू उद्योग ने निर्धारित प्रपत्र के अनुसार आवेदन पत्र दायर किया है।
- 30. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की संगत समझी गई सीमा तक प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है और तदनुसार उन्हें हल किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में विधिवत रूप से की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और वह सूचना गोपनीय मानी गई है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन नहीं की गई है। जहां भी संभव हुआ है, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी व्यापार संबंधित संवेदनशील सूचना को गोपनीय होने का दावा किया है।

च. विविध अनुरोध**च.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध**

31. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- (i) उत्तरदाता निर्यातकों ने अपूर्ण उत्तर दायर किए हैं और कई महत्वपूर्ण सूचनाएं, यथा बेचे गए उत्पादों की सूची और परिशिष्टों में ब्यौरे देने में विफल रहे हैं।
- (ii) वियतनाम में प्राधिकारियों ने मलेशिया और थाईलैंड सहित संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के निर्यातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क जांच शुरू की है।
- (iii) निर्यातकों ने वर्तमान जांच में पर्याप्त रूप से सहयोग नहीं किया है। श्रीलंका और चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक द्वारा प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं किए गए हैं। अतः उन देशों के निर्यातकों को असहयोगी माना जाना है।
- (iv) जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का संबंध है कि संबद्ध देशों से आयातों का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं हो सकता, यह अनुरोध है कि प्राधिकारी द्वारा शुल्क केवल तभी लगाया जाता है, जब कानूनी अपेक्षाएं पूरी की जाएं। जिस अवधि के लिए शुल्क लागू किया गया है, वह संगत नहीं है। यह औचित्य बताना घरेलू उद्योग का काम नहीं है कि उसे संरक्षण की कब तक आवश्यकता है। यह औचित्य बताना निर्यातक का काम है कि वह कब तक पाटन का सहारा लेगा।
- (v) पाटन मार्जिन सत्यापन के अध्यक्षीन है और यह प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाना होता है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान जांच निर्णायक समीक्षा जांच है, अतः कानूनी अपेक्षा यह है कि क्या पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में पाटन और परिणामस्वरूप क्षति की संभावना है। घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन और परिणामस्वरूप क्षति की संभावना के संबंध में साक्ष्य के आधार पर पर्याप्त सूचना उपलब्ध कराई है।
- (vi) मूल जांच में रॉबिन रिसोर्सेस पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संबंधित मामला न्यायाधीन है, जैसा कि हितबद्ध पक्षकारों ने स्वीकार किया है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सीमा शुल्क अधिसूचना वापस नहीं ली गई है। इसके अतिरिक्त, अंतिम निर्णायक समीक्षा में उत्तरदाता निर्यातक का पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक था।

च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

32. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- (i) शुल्क एक दशक से अधिक से लागू रहे हैं और वर्तमान जांच में तथ्य यह दर्शाते हैं कि थाईलैंड और मलेशिया से आयातों का घरेलू उद्योग पर विद्यमान शुल्क समाप्त होने पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं हो सकता।
- (ii) पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन पूरा कर लिया गया है, जैसा कि वर्तमान पाटन एवं क्षति की स्थिति से सिद्ध है।
- (iii) रॉबिन रिसोर्सेस द्वारा निर्यातों के मामले में नकारात्मक पाटन मार्जिन के बावजूद मूल जांच को रद्द न किए जाने से संबंधित मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। प्राधिकारी ने रॉबिन के इस तर्क को अस्वीकार किया कि प्रथम निर्णायक समीक्षा लागू नहीं थी क्योंकि मूल जांच रद्द किए जाने योग्य थी और यूएसडी 5.72 सीबीएम का क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया था। रॉबिन को उचित कानूनी व्यवहार से वंचित किया गया है।
- (iv) रॉबिन रिसोर्सेस का पाटन मार्जिन मूल जांच में नकारात्मक और प्रथम निर्णायक समीक्षा में बहुत कम था। कंपनी के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन का कोई परिणाम और अर्थ नहीं था, जैसा कि पाटन संबंधी न्याय स्थिति यह है कि अकेले पाटन के कारण कोई क्षति पाटनरोधी नियमावली के तहत हल की जाती है। उत्तर में पाटन निर्धारित करने के लिए वर्तमान जांच की अवधि से संबंधित सूचना यह दर्शाएगी कि

निर्यातक अपने घरेलू बाजार की तुलनीय कीमत पर भारत को बिक्री करता आ रहा है और पाटन नहीं किया गया है। विगत 10-15 वर्षों से पाटन एवं नगण्य पाटन मार्जिन के अभाव का इतिहास वर्तमान पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के लिए उचित आधार है।

- (v) रॉबिन रिसोर्सेस से निर्यातों से संबंधित आंकड़े यह दर्शाते हैं कि निर्यातक ने भारत को अधिक निर्यात करने के लिए शुल्क के अभाव का प्रयोग अथवा दुरुपयोग नहीं किया है। पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति पर निर्यात बढ़ेंगे नहीं, जो उसके पूर्व व्यवहार से भी सिद्ध है। वह बिना किसी शुल्क भार के भारत को किसी भी मात्रा में निर्यात कर सकता था, यदि याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए अधिक क्षमता, मालसूची दबाव तीसरे देश के पाटन के आरोप सही थे। कई प्रयोक्ता रॉबिन के उत्पादों को सबसे उपयुक्त पाते हैं और रॉबिन उनकी पूर्ति के लिए कीमत ह्रास की परिपाटियों का सहारा नहीं लेता।
- (vi) वर्तमान जांच थाईलैंड के विरुद्ध रद्द किए जाने की आवश्यकता है, जहां साक्ष्य न तो थाईलैंड से पाटन की संभावना और न ही थाईलैंड से निर्यातित उत्पादों द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की संभावना दर्शाते हैं। इससे सभी शामिल पक्षकारों को पारस्परिक लाभ तथा भारत गणराज्य और थाईलैंड साम्राज्य के बीच द्वितीय अनुकूल व्यापार संबंध होंगे।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

33. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के सभी तर्कों और प्रति तर्कों को नोट किया है और किए गए सभी अनुरोधों की जांच की है।
- (i) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए शुल्क जारी रखने की मुद्दे के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने की सिफारिश केवल तभी की जाती है जब अपेक्षित कानूनी अपेक्षाएं पूरी हों।
- (ii) आवेदन पत्र की पर्याप्तता और परिशुद्ध के संबंध में, हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के बारे में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदन पत्र में जांच की शुरुआत के प्रयोजन के लिए संगत सभी सूचनाएं हैं। प्राधिकारी ने यह संतुष्ट होने के बाद ही कि जांच की शुरुआत का औचित्य बनाने के लिए आवेदन पत्र में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य है, वर्तमान जांच शुरू करने का निर्णय लिया।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1 सामान्य मूल्य

34. धारा 9क(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:
- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-
- (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा
- (ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

35. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:
- (i) आवेदकों ने मलेशिया रिसर्च द्वारा बाजार अनुसंधान रिपोर्ट में सूचित कीमत के आधार पर थाईलैंड, मलेशिया और श्रीलंका के लिए सामान्य मूल्य परिकलित किया है।
 - (ii) आवेदकों ने अनुरोध किया कि प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि वे तब तक सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए चीनी कीमतों अथवा लागतों का प्रयोग न करें, जब तक चीनी निर्यातक यह सिद्ध न कर दें कि विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार की स्थितियां विद्यमान हैं।
 - (iii) आवेदकों ने अनुरोध किया है कि उनकी घरेलू कीमत और लागत पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता, जब तक चीनी निर्यातक यह न दर्शाएं कि लागतें और घरेलू कीमतें उपयुक्त हैं और विचाराधीन उत्पाद की लागत और कीमत को उपयुक्त रूप से दर्शाते हैं।
 - (iv) निर्दिष्ट प्राधिकारी तभी सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अनुबंध-1 के पैरा 1-6 को अपनाएंगे, जब उत्तरदाता चीनी कंपनियां यह सिद्ध करें कि उनकी लागत और कीमत संबंधी सूचना ऐसी है कि अलग सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन निर्धारित किया जा सकता है। यदि उत्तरदाता चीनी कंपनियां यह दर्शाने में समर्थ न हों कि उनकी लागत और कीमत संबंधी सूचना अपनाई जा सकती है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अलग पाटन मार्जिन के दावे को अस्वीकार करेंगे।
 - (v) आवेदक चीन के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु न्यूजीलैंड को उपयुक्त तीसरा देश मानते हैं। आवेदकों ने उस कीमत के आधार पर चीन के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन किया है, जिस पर न्यूजीलैंड से कनाडा में ग्राहकों को सामान बेचे गए हैं।
 - (vi) निर्यात कीमत बाजार सूचना तथा सामान्य अनुभव के आधार पर और सबसे अधिक रूढ़िवादी अनुमानों पर विचार करके विभिन्न समायोजन करने के बाद परिकलित की जाती है।
 - (vii) संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन काफी ही नहीं है, बल्कि अत्यधिक है।
 - (viii) विगत जांचों ने यह सिद्ध किया है कि थाई उत्पादक भारत में विचाराधीन उत्पाद का पाटन कर रहे थे।
 - (ix) जहां तक ट्रेड मैप के आंकड़ों का संबंध है, घरेलू उद्योग ने अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार सूचना उपलब्ध कराई है।

छ.3 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

36. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:
- (i) जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात सामान्य मूल्य से काफी अधिक निर्यात कीमत पर लगभग 500-800 मी. टन हैं।
 - (ii) पाटन मार्जिन का परिकलन अलग लागत तालिका और रॉबिन रिसोर्सेस (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी. द्वारा प्रस्तुत तीनों ग्रेडों की कीमत के आधार पर ग्रेड-वार किया जाना चाहिए।
 - (iii) औसत कीमत के आधार पर आंकड़ों में दावा किया गया पाटन मार्जिन भ्रामक है क्योंकि यह तीसरे देशों का 70122 मी. टन निर्यात दर्शाता है जिसमें से 23911 मी. टन (35 प्रतिशत) भारत को भेजे जाने पर अत्यधिक सकारात्मक पाटन मार्जिन की संभावना वाला दावा किया गया है। उत्तरों में दिए गए पीसीएन-वार आंकड़े यह दर्शाएंगे कि यदि निर्यात भेजे जाते हैं तो वे ऐसा कोई पाटन प्रभाव नहीं बनाएंगे। यहां तक कि पाटन प्रभाव की संभावना वाला दावा किया गया 23911 मी. टन भारतीय मांग की तुलना में बहुत कम मात्रा है और इन मात्राओं से भारतीय बाजार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ेगा।

- (iv) थाईलैंड के आंकड़ों के आधार पर तीसरे देश की औसत निर्यात कीमत के आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया थाईलैंड और मलेशिया के लिए पाटन मार्जिन अविश्वसनीय है और उचित तुलना सुनिश्चित नहीं करता। यदि ये ट्रेडमैप आंकड़े विश्वसनीय थे तो याचिकाकर्ताओं को यह स्पष्ट करना है कि डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के बजाए टी/टी आंकड़ों का प्रयोग क्यों किया गया था। जांच की अवधि के लिए पाटन मार्जिन आंकड़ों की पर्याप्तता और परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरों के आधार पर निर्धारित किया जाना है।
- (v) निर्यातक किसी भी बाजार में उत्पाद का पाटन करने की मांग नहीं करते। अनुचित व्यापार के संबंध में टीपीपीआईसी सदस्यों के विरुद्ध कोई मामला नहीं लाया गया है और वियतनाम द्वारा लाया गया हाल का मामला उपायों के बिना रह किया गया था।

छ.4 प्राधिकारी द्वारा जांच

37. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां उन्हें यह सलाह देते हुए भेजीं कि वे प्राधिकारी द्वारा निर्धारित स्वरूप एवं तरीके में सूचना उपलब्ध कराएं। निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्धारित प्रश्नावली के उत्तर दायर कर इस जांच में सहयोग किया है:
- (i) पैनल प्लस एमडीएफ कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
 - (ii) रॉबिन रिसोर्सेस (मलेशिया) एसडीएन, बीएचडी, मलेशिया

चीन जन. गण. के लिए बाजार अर्थव्यवस्था

38. चाइनीज एसेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

- (क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:
 - (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
 - (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।
- (ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

- (ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।
- (घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

39. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि चीन जन. गण. के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क)(ii) के प्रावधान 11 दिसंबर, 2016 से समाप्त हो गए हैं, तथापि अभिगम नयाचार के 15(क)(i) के तहत दायित्वों के साथ पठित पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के स्तर का दावा करने के संबंध में पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड को पूरा किए जाने की अपेक्षा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी चीन जन. गण. के किसी भी निर्यातक/ उत्पादक ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्राधिकारी सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार कार्यवाही करना उपयुक्त समझते हैं।

छ.4.1 चीन जन. गण. से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

40. चीन जन. गण. के किसी भी उत्पादक ने वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया है और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(2) के अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का खंडन करने के लिए कोई सूचना नहीं दी है। अतः पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(2) के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा अखंडित रहती है। अतः प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।
41. प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में निर्धारित क्रम के अनुसार सामान्य मूल्य के निर्माण के विकल्प का पता लगाया है जिसमें यह प्रावधान है कि सामान्य मूल्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य अथवा भारत सहित अन्य देशों को ऐसे तीसरे देश से कीमत के आधार पर अथवा जहां यह संभव न हो, वहां उपयुक्त लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए यदि आवश्यक हो तो विधिवत समायोजित करके समान उत्पाद के लिए भारत में देय अथवा वास्तविक रूप से दी गई कीमत सहित किसी अन्य उपयुक्त आधार पर निर्धारित की जाएगी।
42. प्राधिकारी ने बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक तथा उपयुक्त लाभ सहित विधिवत समायोजित करके भारत में उत्पादन लागत के आधार पर चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य निर्मित किया है। चीनी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित वह निर्मित सामान्य मूल्य निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

छ.4.2 थाईलैंड से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

पैनल प्लस एमडीएफ कंपनी लिमिटेड

43. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पैनल प्लस एमडीएफ कं. लि. थाईलैंड में आधारित संबद्ध सामानों का उत्पादक एवं निर्यातक है। उसके संबद्ध व्यापारी, अर्थात् पैनल प्लस कं. लि. ने भी प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं। पैनल प्लस एमडीएफ कं. लि. ने घरेलू बाजार में की गई बिक्री के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। जांच की अवधि के दौरान निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में उपलब्ध सूचना के अनुसार पैनल प्लस एमडीएफ कं. लि. की घरेलू बिक्री के संबंध में किए गए व्यापार (80:20) परीक्षण की सामान्य प्रक्रिया के दौरान *** प्रतिशत की बिक्री लाभप्रद दर्शाती है। अतः जांच की अवधि में संबद्ध सामानों का सामान्य मूल्य संबद्ध देश में केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री लेकर ही निर्धारित किया गया है। पैनल प्लस एमडीएफ कं. ने अंतर्देशीय भाड़ा एवं बैंक प्रभारों के निमित्त

समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने उचित सत्यापन के बाद उसकी अनुमति दी है और इस प्रकार निकाला गया सामान्य मूल्य निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

थाईलैंड से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

44. थाईलैंड से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

छ.4.3 मलेशिया से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

रॉबिन रिसोर्सेस (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी

45. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रॉबिन रिसोर्सेस (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी मलेशिया में आधारित संबद्ध सामानों का उत्पादक एवं निर्यातक है। रॉबिन रिसोर्सेस (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी ने घरेलू बाजार में की गई बिक्री के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। जांच की अवधि के दौरान निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में उपलब्ध सूचना के अनुसार रॉबिन रिसोर्सेस (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी की घरेलू बिक्री के संबंध में किए गए व्यापार (80:20) परीक्षण की सामान्य प्रक्रिया के दौरान *** प्रतिशत की बिक्री लाभप्रद दर्शाती है। अतः जांच की अवधि में संबद्ध सामानों का सामान्य मूल्य मलेशिया में कुल घरेलू बिक्री की औसत कीमत लेकर निर्धारित किया गया है। रॉबिन रिसोर्सेस (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी ने अंतर्देशीय भाड़ा, ऋण लागत एवं बैंक प्रभारों के निमित्त समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने उचित सत्यापन के बाद उसकी अनुमति दी है और इस प्रकार निकाला गया सामान्य मूल्य निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

मलेशिया से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

46. मलेशिया से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

छ.4.4 श्रीलंका से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

47. प्राधिकारी नोट करते हैं कि श्रीलंका से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं किए हैं। श्रीलंका में सभी उत्पादकों/निर्यातकों से असहयोग के मद्देनजर, प्राधिकारी ने नियम 6(8) के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है और वह निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

छ.4.5 निर्यात कीमत

थाईलैंड से उत्पादकों/ निर्यातकों के संबंध में निर्यात कीमत का निर्धारण

पैनल प्लस एमडीएफ कं० लि० (उत्पादक/ निर्यातक)

48. पैनल प्लस एमडीएफ कं० लि० ने अपने संगत व्यापारी, नामतः पैनल प्लस कं० लि० के साथ प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया है। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पैनल प्लस एम डी एफ कं० लि० ने जांच की अवधि के दौरान सीधे भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। निर्यातक द्वारा अपने प्रश्नावली उत्तर में दावा किए गए स्वदेशी मालभाड़ा, बंदरगाह और अन्य संगत व्ययों, क्रेडिट लागत और बैंक प्रभारों के संबंध में समायोजन किया गया है ताकि कारखाना बाह्य स्तर पर निवल निर्यात कीमत निकाली जा सके। तदनुसार, पैनल प्लस एम डी एफ कं० लि० के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की गई है, जो नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

थाईलैंड से अन्य उत्पादक और निर्यातक

49. चूंकि थाईलैंड से संबद्ध वस्तुओं के किसी अन्य उत्पादक/ निर्यातक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, अतः प्राधिकारी ने थाईलैंड से किसी अन्य उत्पादक/ निर्यातक के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (8) के प्रावधानों के तहत, उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्यात कीमत का निर्धारण किया है।

मलेशिया से उत्पादकों/ निर्यातकों के संबंध में निर्यात कीमत का निर्धारण**रॉबिन रिसोर्सेज (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी.**

50. रॉबिन रिसोर्सेज (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी. ने जांच की अवधि के दौरान सीधे भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। निर्यातक द्वारा अपने प्रश्नावली उत्तर में दावा किए गए समुद्री मालभाड़ा, बीमा, स्वदेशी मालभाड़ा, बंदरगाह और अन्य संगत व्ययों तथा कमीशन के संबंध में समायोजन किया गया है ताकि कारखाना बाह्य स्तर पर निवल निर्यात कीमत निकाली जा सके। तदनुसार रॉबिन रिसोर्सेज (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी. के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है, जिसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

मलेशिया से अन्य उत्पादक और निर्यातक

51. चूंकि मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, अतः प्राधिकारी ने मलेशिया से किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के प्रावधानों के तहत, उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्यात कीमत का निर्धारण किया है।

चीन जन. गण. और श्रीलंका से असहयोगी निर्यातकों/ उत्पादकों के संबंध में निर्यात कीमत का निर्धारण

52. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि श्रीलंका और चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया है। उनके असहयोग को देखते हुए, प्राधिकारी ने चीन जन. गण. और श्रीलंका से निर्यातकों के संबंध में नियम 6 (8) के प्रावधानों के अनुसार, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्यात कीमत का निर्धारण किया है।

छ.4.6 पाटन मार्जिन

53. उपरोक्तानुसार सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के सभी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण इस प्रकार किया गया है :-

क्र. सं.	उत्पादक	निर्यात मात्रा	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन %	रेंज
		सीबीएम	यूएस डॉलर/ मी. टन	यूएस डॉलर/ मी. टन	यूएस डॉलर/ मी. टन	%	%
1.	पैनल प्लस एमडीएफ कं० लि०, थाईलैंड	***	***	***	***	***	10-20
2.	थाईलैंड से असहयोगी उत्पादक/ निर्यातक	***	***	***	***	***	25-35
3.	रॉबिन रिसोर्सेज (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी., मलेशिया	***	***	***	***	***	0-10
4.	मलेशिया से असहयोगी उत्पादक/ निर्यातक	***	***	***	***	***	15-25
5.	चीन जन. गण. से सभी उत्पादक/ निर्यातक	***	***	***	***	***	नकारात्मक
6.	श्रीलंका से सभी उत्पादक/ निर्यातक	***	***	***	***	***	30-40

ज. क्षति निर्धारण के लिए कार्यप्रणाली और क्षति तथा कारणात्मक संबंध की जांच

54. नियमावली के अनुबंध-II के साथ पठित नियम 11 के तहत यह प्रावधान है कि एक क्षति निर्धारण में ऐसे कारकों की जांच करना शामिल होगा, जो घरेलू उद्योग को क्षति दर्शा सकते हैं “..... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव तथा ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए...../” कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए, यह जांच करना आवश्यक समझा गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमतों की तुलना में पाटित आयातों से पर्याप्त कीमत कटौती हो रही है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव पर्याप्त मात्रा में कीमतों को अन्यथा दबाने के लिए है अथवा कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा एक पर्याप्त मात्रा में होती।
55. नियमावली के नियम 23 के तहत यह प्रावधान है कि नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19 और 20 के प्रावधान एक समीक्षा के मामले में यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे। प्राधिकारी ने अपनी जांच में ऐसे क्षति मापदंडों का मूल्यांकन किया है, जो नियमावली के नियम 11 तथा अनुबंध-II के तहत अपेक्षित है और यह भी जांच की गई है कि क्या शुल्क समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
56. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए आवेदन मै० ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज लि०/ ग्रीनपैनल इंडस्ट्रीज लि०, सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स (इंडिया) लि० और रुशिल डेकोर लि० द्वारा दाखिल किया गया है नियमावली के नियम 2 (ख) के अनुसार, आवेदकों को इस जांच के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग के रूप में माना गया है। अतः आवेदकों की लागत और क्षति संबंधी सूचना, जिसमें घरेलू उद्योग शामिल है, की जांच की गई है।

ज.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

57. क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध नीचे दिए गए हैं:-
- क्षति की संभावना के निर्धारण के दौरान संभावित पाटित आयातों के प्रभावों का संचित आकलन वर्तमान जांच में उपयुक्त है।
 - समूची क्षति अवधि के दौरान मात्रा में वृद्धि हुई है और वृद्धि पर्याप्त रही है।
 - समूची क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों में जांच की अवधि के दौरान मामूली गिरावट आई है। तथापि, जांच की अवधि में आयातों का स्तर पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद, आधार वर्ष और 2016-17 की तुलना में अधिक है।
 - संबद्ध देशों के पास देश में संबद्ध वस्तुओं के कुल आयातों में 28 प्रतिशत का पर्याप्त हिस्सा है।
 - देश में मांग और आपूर्ति के अंतर को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि होने और पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी होने के बावजूद संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि हुई है।
 - सभी संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। श्रीलंका और मलेशिया से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है।
 - घरेलू उद्योग संबद्ध देशों से पाटित आयातों की कीमतों के कारण कीमतों के दमन और कीमतों पर दबाव का सामना कर रहा है। जांच की अवधि के दौरान, जब वर्ष 2017-18 की तुलना में घरेलू उद्योग की लागत में वृद्धि हुई है तो घरेलू उद्योग पाटित आयातों के कारण अपनी बिक्री कीमत कम करने पर मजबूर हुआ है।
 - पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग को नकदी लाभ में गिरावट और निवेशों पर प्रतिफल में गिरावट का सामना करना पड़ा है। शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर और भी प्रभाव पड़ा है।
 - घरेलू उद्योग के पास इन्वेंट्री में, कम अनुकूल कीमतों के प्रस्ताव के बावजूद पूरी क्षति अवधि के दौरान काफी वृद्धि हुई है।

- x. यद्यपि वर्ष 2016-18 और 2017-18 की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का निष्पादन तर्कसंगत था, लेकिन घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटन के कारण से पुनः निष्पादन में गिरावट का सामना करना पड़ा है।
- xi. संबद्ध देशों से आयात जांच की अवधि में पाटित कीमतों पर जारी रहे हैं।
- xii. संबद्ध देशों से आयातों में कटौती हो रही है और घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है।
- xiii. संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास सरप्लस क्षमताएं हैं। पाटनरोधी शुल्क समाप्त हो जाने की स्थिति में, ये सरप्लस क्षमताएं भारत की ओर आंतरित की जाएंगी।
- xiv. शुल्क समाप्त होने की स्थिति में, संबद्ध आयातों में परिणामी वृद्धि होने के कारण घरेलू उद्योग अपनी कीमतों में पर्याप्त कटौती करने पर बाध्य होगा।
- xv. यदि कीमतों में कटौती होती है, तो घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर प्रभाव पड़ेगा। लाभों में आगे गिरावट आने से नकदी प्रवाह में और निवेशों पर प्रतिफल में एक बड़ी गिरावट आएगी।
- xvi. यदि घरेलू उद्योग अपने सामान्य कीमत स्तर को बरकरार रखने का चयन करता है तो उसे बिक्री की मात्रा का घटा होने की संभावना है।
- xvii. यदि बिक्री की मात्रा के घाटे को घरेलू उद्योग द्वारा अधिमानता दी जाती है तो उसे अधिक बड़ी क्षति होगी, क्योंकि इन्वेंट्री में तो वृद्धि होगी लेकिन उत्पादन, क्षमता उपयोग और उत्पादकता में गिरावट आएगी।
- xviii. मलेशिया से आयातों में पर्याप्त वृद्धि हुई है।
- xix. भारत के समग्र हित में कीमत स्तरों के संबंध में, यह अनुरोध किया जाता है कि घरेलू उद्योग जिम्मेदार और जवाबदेह है। सामान्यतः पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजन पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करना है, ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुनः स्थापित किया जा सके, जो कि देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय लगाना, किसी भी तरह से संबद्ध देश/ परिक्षेत्र से आयातों को सीमित करना नहीं होगा और इसीलिए उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- xx. वार्षिक रिपोर्ट में सार्वजनिक विवरणों से यह निष्कर्ष बदलता नहीं है कि उत्पाद के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। यह गलत माना गया है कि क्षति का एकमात्र कारण पाटन है। वार्षिक रिपोर्ट में विवरण, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट के संबंध में नहीं है और वे कंपनी के समग्र प्रचालनों के संबंध में है।

ज.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

58. क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध नीचे दिए गए हैं :

- i. जैसा कि सार्वजनिक वार्षिक रिपोर्ट से नोट किया गया है, भारतीय उत्पादक नई क्षमताओं की स्थापना के साथ भी प्रभावशाली विकास दर प्राप्त कर रहे हैं।
- ii. थाईलैंड से निर्यातों की मात्रा कुल आयातों और बाजार अंश, दोनों के संदर्भ में नगण्य हैं।
- iii. थाईलैंड से निर्यातों के कारण कथित क्षति नहीं हुई है और न ही कथित क्षति जारी है।
- iv. थाई आयातक विश्व में कहीं भी पाटन नहीं कर रहे हैं और वे उचित कीमतों पर बिक्री करने में विश्वास करते हैं।
- v. ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज लि०/ ग्रीनपैनल इंडस्ट्रीज लि० ने वर्ष 2018 और 2019 में बेहतर लाभ मार्जिन के साथ राजस्व में मजबूत विकास को देखा है।
- vi. वर्ष 2019 में लाभों में सापेक्ष गिरावट वित्तीय लागतों में वृद्धि होने के कारण से हैं और ये अधिकतर, क्षमता में वृद्धि होने से संबद्ध होने की संभावना है।

- vii. सेंचुरी प्लाई के लिए निष्पादन में भी सार्वजनिक दस्तावेजों के अनुसार सकारात्मक वृद्धि देखी गई है।
- viii. सार्वजनिक दस्तोवेजों में, विचाराधीन उत्पाद के आयातों और पाटन के कारण किसी समस्या का कोई उल्लेख नहीं है।
- ix. विचाराधीन उत्पाद के लिए थाईलैंड से वास्तविक निर्यात करीब 500-800 मी. टन रहा है, जो कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रयुक्त आयात संबंधी आंकड़ों से कम है।
- x. जांच की अवधि के दौरान, कुल आयातों का हिस्सा 1 प्रतिशत से भी कम है और भारतीय घरेलू बाजार के बाजार अंश और खपत के संदर्भ में यह 1 प्रतिशत से भी काफी कम है। बिक्री कीमतें संबद्ध देशों में सबसे अधिक है और ऐसे 21 देशों के बीच सबसे अधिक कीमत है, जिन्होंने जांच के दौरान संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति की थी।
- xi. भारतीय आयात संबंधी आंकड़ों के आधार पर, थाई की सी आई एफ कीमतें जांचाधीन निर्यातक देशों में सबसे अधिक हैं।
- xii. जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा स्वीकार किया गया है, कोई कीमत कटौती नहीं हो रही है। कीमत का कोई प्रभाव तो हो सकता है, लेकिन उसकी मात्रा अपर्याप्त है।
- xiii. उद्योग की एन आई पी की गणना का तात्पर्य यह होगा कि लगभग सभी देशों में कम बिक्री हो रही है।
- xiv. निवेशों में वृद्धि होने के कारण वित्तीय लागतों के चलते उत्पादन की लागत की पुनः जांच की जानी चाहिए।
- xv. क्षमताओं में वृद्धि के लिए अधिक लागतों के बावजूद याचिकाकर्ताओं ने लाभ कमाया है।
- xvi. नए निवेशों से जुड़ी लागतों में वृद्धि होने के कारण लाभों में कटौती की संभावना अधिक है।
- xvii. संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई भी निरंतर क्षति नहीं हुई है। घरेलू उद्योग निर्यातकों से हुए आयातों पर निर्भर नहीं है। मात्रा संबंधी मापदंडों में वृद्धि हुई है और कीमत संबंधी मापदंड सकारात्मक रहे हैं। लाभप्रदता में मामूली गिरावट होना संबद्ध आयातों के कारण से है क्योंकि अन्य देशों से अधिक आयात हो रहे हैं।
- xviii. घरेलू उद्योग कीमतों में वृद्धि की इच्छा रखता है, जब उनका निष्पादन काफी प्रभावकारी रहता है। हितबद्ध पक्षकारों ने सेंचुरी प्लाई बोर्ड्स इंडिया के अध्यक्ष सज्जन भजनका के विवरणों पर भरोसा किया है, जिसने कि यह कहा है कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निष्पादन वृद्धि का महत्वपूर्ण संचालक ए डी एफ का बिजनेस था और वित्त वर्ष 2019 में 65 प्रतिशत का क्षमता उपयोग हासिल किया गया है, वित्त वर्ष 2018 में एच 113.11 करोड़ से वित्त वर्ष 2019 में एच 295.35 करोड़ के राजस्व में 161.11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- xix. याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा की गई क्षति और कारणात्मक संबंध सत्य नहीं है। याचिकाकर्ताओं के सभी मात्रा संबंधी मापदंडों जैसे क्षमता, उत्पादन, बिक्री आदि में वृद्धि हुई है और यहां तक कि कीमत संबंधी मापदंड भी सकारात्मक रहे हैं और लाभप्रदता में कोई भी मामूली सी गिरावट संबद्ध आयातों के कारण से नहीं हो सकती क्योंकि अन्य देशों से उच्च स्तर के आयात हो रहे थे। संबद्ध आयातों के कारण से घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति नहीं हुई थी और दावा की गई क्षति संबद्ध आयातों से संबद्ध नहीं हो सकती।
- xx. घरेलू उद्योग वर्षों से स्थायी ढंग में निष्पादन नहीं कर रहा है और जांच की अवधि तथा क्षति अवधि के दौरान कोई निरंतर क्षति नहीं दर्शाई गई है। समग्र स्थिति, थाईलैंड से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में लागू वर्तमान पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति को स्पष्ट करती है।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

59. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के तहत (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव ; और (ख) ऐसे आयातों के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव, दोनों की उद्देश्यपरक जांच के लिए प्रावधान है।

60. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क (5) के अनुसार, लगाए गए पाटनरोधी शुल्क, जब तक पहले हटा नहीं लिए जाते, इस प्रकार से लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर उनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा, बशर्ते कि यदि केंद्रीय सरकार की किसी समीक्षा में यह राय है कि ऐसे शुल्क समाप्त होने के पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, समय-समय पर, आगे की पांच वर्षों की अवधि के लिए यह शुल्क लगाने की अवधि बढ़ा सकती है और इस प्रकार से बढ़ाई गई अवधि इस विस्तार के आरंभ की तारीख से शुरू होगी।
61. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को देखते हुए, प्राधिकारी संबद्ध देशों से आयातों के संबंध में पाटन और क्षति के संभावित पहलुओं की जांच शुरू करने से पूर्व घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति, यदि कोई हो, की जांच की कार्यवाही शुरू करते हैं।
62. यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मापदंडों में गिरावट हो। कुछ मापदंडों में गिरावट आ सकती हैं, जबकि कुछ अन्य में गिरावट नहीं नहीं भी आ सकती। प्राधिकारी सभी क्षति मापदंडों पर विचार करते हैं और उसके बाद यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घरेलू उद्योग को पाटन के कारण क्षति हुई है अथवा नहीं। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति संबंधी मापदंडों की उद्देश्यपरक जांच की है।

ज.3.1 मांग का आकलन

63. प्राधिकारी ने भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से हुए आयातों के योग के रूप में भारत में उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत का निर्धारण किया है। इस प्रकार से आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है:-

भारत में मांग	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि	
					वार्षिकीकृत	वास्तविक
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	सीबीएम	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	95	106	134	134
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्रियां	सीबीएम	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	104	104	119	119
संबद्ध देशों से आयात	सीबीएम	34,287	33,391	44,423	39,446	59,170
चीन	सीबीएम	179	400	466	74	112
मलेशिया	सीबीएम	12,501	18,848	27,904	30,716	46,074
थाईलैंड	सीबीएम	3,406	2,271	3,681	1,914	2,872
श्रीलंका	सीबीएम	18,201	11,872	12,371	6,741	10,112
पाटनरोधी शुल्क वाले अन्य देश	सीबीएम	61,099	92,335	1,41,284	97,447	1,46,171
इंडोनेशिया	सीबीएम	16,977	6,724	856	97	145
वियतनाम	सीबीएम	44,123	85,611	1,40,427	97,350	1,46,026
अन्य देशों से आयात	सीबीएम	17,881	23,094	22,302	18,306	27,459
भारत में कुल मांग	सीबीएम	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	108	123	128	128
मांग में बाजार अंश						
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	88	86	105	105
अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***	***

प्रवृत्ति		100	97	85	93	93	
अन्य देशों से आयात	%	7	6	7	6	6	
चीन	%	0	0	0	0	0	
मलेशिया	%	3	4	5	5	5	
थाईलैंड	%	1	0	1	0	0	
श्रीलंका	%	4	2	2	1	1	
पाटनरोधी शुल्क वाले अन्य देश	%	12	17	23	15	15	
इंडोनेशिया	%	3	1	0	0	0	
वियतनाम	%	9	16	23	15	15	
अन्य देश	%	4	4	4	3	3	
कुल मांग	%	100	100	100	100	100	

64. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि समूची क्षति अवधि और जांच की अवधि के दौरान भारत में मांग में वृद्धि हुई है।

ज.3.2 पाटित आयातों का मात्रा संबंधी प्रभाव

65. संबद्ध देशों से पाटित आयातों तथा अन्य देशों से आयातों के मात्रा संबंध प्रभाव की प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है, जो इस प्रकार है :-

आयात की मात्रा	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि	
					वार्षिकीकृत	वास्तविक
संबद्ध देशों से आयात	सीबीएम	34,287	33,391	44,423	39,446	59,170
चीन	सीबीएम	179	400	466	74	112
मलेशिया	सीबीएम	12,501	18,848	27,904	30,716	46,074
थाईलैंड	सीबीएम	3,406	2,271	3,681	1,914	2,872
श्रीलंका	सीबीएम	18,201	11,872	12,371	6,741	10,112
पाटनरोधी शुल्क वाले अन्य देश	सीबीएम	61,099	92,335	1,41,284	97,447	1,46,171
इंडोनेशिया	सीबीएम	16,977	6,724	856	97	145
वियतनाम	सीबीएम	44,123	85,611	1,40,427	97,350	1,46,026
अन्य देशों से आयात	सीबीएम	17,881	23,094	22,302	18,306	27,459
कुल मात्रा आयात	सीबीएम	1,13,267	1,48,820	2,08,008	1,55,199	2,32,799
निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध देशों से आयात						
आयात	%	30.27	22.44	21.36	25.42	25.42
उत्पादन	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	94	120	81	81
खपत	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	122	149	107	107

66. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों की मात्रा में वर्ष 2017-18 के दौरान वृद्धि हुई है और जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है। तथापि, आधार वर्ष 2015-16 की तुलना में संबद्ध देशों से आयातों में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।

ज.3.3 पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव

67. नियमावली के अनुबंध-II (ii) के अनुसार प्राधिकारी को कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत दमन और कीमत दबाव, यदि कोई हो, के संदर्भ में घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करना अपेक्षित है।

I. कीमत कटौती

68. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से पर्याप्त कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव एक महत्वपूर्ण मात्रा में कीमतों को अन्यथा दबाने अथवा कीमत में वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा एक महत्वपूर्ण मात्रा में हो गई होती। इस संबंध में, संबद्ध देशों से उत्पाद के पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत, समान व्यापार स्तर पर सभी निवल रिबेट और करों के बीच एक तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतें कारखाना बाह्य कीमत स्तर पर निर्धारित की गई थी।

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
कुल बिक्री प्राप्ति	रू./ सीबीएम	***	***	***	***
समग्र संबद्ध देश					
बिना पाटनरोधी शुल्क के आयातों की पहुंच कीमत	रू./ सीबीएम	18,215	15,734	15,582	15,063
कीमत कटौती	रू./ सीबीएम	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	10-20	20-30	20-30	20-30
चीन					
बिना पाटनरोधी शुल्क के आयातों की पहुंच कीमत	रू./ सीबीएम	26,495	21,588	19,495	22,214
कीमत कटौती	रू./ सीबीएम	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	नकारात्मक	नकारात्मक	10-20	नकारात्मक
मलेशिया					
बिना पाटनरोधी शुल्क के आयातों की पहुंच कीमत	रू./ सीबीएम	16,621	14,589	14,979	14,899
कीमत कटौती	रू./ सीबीएम	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	20-30	30-40	30-40	20-30
थाईलैंड					
बिना पाटनरोधी शुल्क के आयातों की पहुंच कीमत	रू./सीबीएम	16,980	17,304	17,333	15,354
कीमत कटौती	रू./सीबीएम	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***

कीमत कटौती	रेंज	20-30	10-20	20-30	20-30
श्रीलंका					
बिना पाटनरोधी शुल्क के आयातों की पहुंच कीमत	रू./ सीबीएम	19,461	17,054	16,274	15,651
कीमत कटौती	रू./ सीबीएम	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	10-20	20-30	20-30	20-30

69. यह नोट किया जाता है कि मलेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका से आयात कीमतों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। चीन के संबंध में कीमत कटौती नकारात्मक है।

ii. कीमत ह्रास/ न्यूनीकरण

70. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयातों से घरेलू कीमतों का ह्रास अथवा उनका न्यूनीकरण हो रहा है और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव महत्वपूर्ण मात्रा में कीमतों पर दबाव डालने अथवा कीमत में वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा एक महत्वपूर्ण मात्रा में हो गई होती, अतः प्राधिकारी क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तनों को नोट करते हैं। यह स्थिति को नीचे दी गई तालिका के तहत दर्शाया गया है :-

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
बिक्रियों की लागत	रू./ सीबीएम	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	94	100	100
बिक्री कीमत	रू./ सीबीएम	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	99	102	90
संबद्ध देशों से पहुंच कीमत	रू./ सीबीएम	18,215	15,734	15,582	15,063
प्रवृत्ति		100	86	86	83

71. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत जांच की अवधि के दौरान बिक्रियों की लागत से कम है। परिणामस्वरूप, जब क्षति अवधि के दौरान लागत में गिरावट आई है, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में लागत में गिरावट से अधिक गिरावट आई है। आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों का दमन हो रहा है।

iii. कम कीमत पर बिक्री

72. संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत के साथ गैर क्षतिकारी कीमत की तुलना करके कम कीमत पर बिक्री की मूल्यांकन किया गया है।

विवरण	यूओएम	चीन जन. गण.	मलेशिया	थाईलैंड	श्रीलंका
आयात की मात्रा	सीबीएम	***	***	***	***
गैर-क्षतिकारी कीमत (एन आई पी)	रू./ सीबीएम	***	***	***	***
पहुंच मूल्य	रू./ सीबीएम	22,213.7	14,898.8	15,354.1	15,651.4
क्षति मार्जिन	रू./ सीबीएम	***	***	***	***
क्षति मार्जिन	%	***	***	***	***
क्षति मार्जिन	%, रेंज	नकारात्मक	10-20	10-20	10-20

73. यह देखा गया है कि चीन जन. गण. के अलावा प्रत्येक संबद्ध देश के लिए कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक है।

ज.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर प्रभाव

74. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के तहत यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादकों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की एक उद्देश्यपरक जांच शामिल होगी। पाटनरोधी नियमावली के तहत यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्रियों, लाभों, आउटपुट, बाजार अंश, उत्पादकता, निवेशों पर प्रतिफल, अथवा क्षमता के उपयोग, घरेलू कीमतों, पाटन के मार्जिन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों, नकदी प्रवाह, इन्वेंट्री, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता सहित उद्योग की स्थिति पर संबंध रखने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों का एक उद्देश्यपरक मूल्यांकन शामिल होगा। तदनुसार, घरेलू उद्योग के संबंध में विभिन्न क्षति मापदंडों को नीचे दर्शाया गया है।

क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियां

75. प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्रियों की मात्रा पर विचार किया है और यह नोट करते हैं कि :-

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि	
					वार्षिकीकृत	वास्तविक
संस्थापित क्षमता - संयंत्र	सीबीएम	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	100	137	284	284
उत्पादन की मात्रा - संयंत्र	सीबीएम	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	108	128	185	185
क्षमता उपयोग - संयंत्र	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	108	94	65	65
उत्पादन की मात्रा- पीयूसी	सीबीएम	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	103	113	171	171
घरेलू बिक्रियां - पीयूसी	सीबीएम	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	95	106	134	134

76. उपरोक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि :-

क. घरेलू उद्योग की क्षमता में वर्ष 2017-18 और जांच की अवधि में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी यह विचार करते हैं कि क्षमता में वृद्धि सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स और ग्रीनप्लाई/ ग्रीनपैनल और सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स द्वारा नई क्षमताओं के कारण से है।

ख. घरेलू उद्योग की उत्पादन मात्रा में वर्ष 2017-18 और जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।

ग. वर्ष 2017-18 में और उसके बाद जांच की अवधि में क्षमता के उपयोग में गिरावट आई है।

घ. घरेलू बिक्रियों में भी उत्पादन की प्रवृत्ति ही दर्शाई गई है।

ख. मांग में घरेलू उद्योग का बाजार अंश

77. घरेलू उद्योग के बाजार अंश की जांच की गई है, जो इस प्रकार से है :-

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि	
					वास्तविक	
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***	
प्रवृत्ति		100	88	86	105	
अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***	

प्रवृत्ति		100	97	85	93
संबद्ध देशों से आयात	%	7	6	7	6
पाटनरोधी शुल्क वाले अन्य देश (वियतनाम और इंडोनेशिया)	%	12	17	23	15
अन्य देश	%	4	4	4	3
कुल मांग	%	100	100	100	100

78. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों का बाजार अंश कुल मिलाकर वही रहा, जबकि घरेलू उद्योग के बाजार अंश में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि बाजार अंश में वृद्धि क्षमता में वृद्धि और बाजार में बने रहने के लिए कम अनुकूल कीमतों के कारण है।

ग. इन्वेन्ट्री

79. संबद्ध वस्तुओं की इन्वेन्ट्री के संबंध में डाटा नीचे तालिका में दर्शाए गए हैं :-

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
इन्वेन्ट्री – औसत	सीबीएम	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	151	318	431

80. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की इन्वेन्ट्री में क्षति की अवधि और इसके बाद जांच की अवधि के दौरान पर्याप्त वृद्धि हुई है।

घ. लाभ अथवा हानि, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिफल

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि	
					वार्षिकीकृत	वास्तविक
बिक्रियों की लागत	रू./ सीबीएम	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	94	100	100	100
बिक्री कीमत	रू./ सीबीएम	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	99	102	90	90
कर पूर्व लाभ	रू./ सीबीएम	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	116	113	51	51
कर पूर्व कुल लाभ	रू. लाख	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	111	120	68	68
ब्याज पूर्व कुल लाभ	रू. लाख	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	105	114	77	77
नकद लाभ	रू. लाख	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	107	133	96	96
लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	122	76	29	29

81. घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच की गई है।
82. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकदी लाभों और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल में वर्ष 2016-17 तक निरंतर वृद्धि हुई है और उसके बाद जांच की अवधि में गिरावट आई है।

ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

83. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति इस प्रकार है:

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि	
					वार्षिकीकृत	वास्तविक
रोजगार	संख्या	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	102	155	237	237
उत्पादकता प्रति दिन	सीबीएम	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	103	113	171	171
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	सीबीएम	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	101	73	72	72
मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	101	134	247	247

84. यह नोट किया जाता है कि रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता प्रति दिन में वर्ष 2017-18 और जांच की अवधि में पर्याप्त वृद्धि दर्शाई गई है। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि ये मापदंड घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं।

च. विकास

85. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के विकास संबंधी मापदंडों की जांच नीचे दर्शाई गई है :-

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
					वार्षिक
उत्पादन (पीयूसी)	%	-	2.79	9.92	51.51
घरेलू बिक्रियों की मात्रा	%	-	(4.78)	11.81	25.96
क्षमता उपयोग	%	-	8.02	(13.03)	(30.71)
लाभ/ हानि घरेलू (प्रति सीबीएम)	%	-	16.09	(2.76)	(54.90)
आरओआई	%	-	22.03	(37.80)	(61.18)
नकद लाभ	%	-	7	20	(26)

86. यह नोट किया जाता है कि उत्पादन और बिक्रियों के संदर्भ में घरेलू उद्योग का विकास सकारात्मक है, जबकि क्षमता उपयोग, लाभों, और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल के संदर्भ में विकास नकारात्मक है।

छ. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

87. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि देश में पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण घरेलू कीमतों पर प्रभाव पड़ा है।

ज. नए निवेश जुटाने की क्षमता

88. घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग, देश में पर्याप्त मांग के बावजूद कम क्षमता उपयोग पर प्रचालन कर रहा है और इससे घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता कमजोर हुई है।

क्षति के संबंध में निष्कर्ष

89. पर्याप्त क्षति के संबंध में विभिन्न मापदंडों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों की मात्रा में सापेक्ष दृष्टि से वृद्धि हुई है। जांच की अवधि में आयातों से घरेलू कीमतों में कटौती हो रही है और घरेलू उद्योग घरेलू बिक्री कीमतों पर एक दमनकारी प्रभाव का सामना कर रहा था। घरेलू उद्योग के समग्र निष्पादन में, क्षमता उपयोग, लाभों, नकदी लाभों और जांच की अवधि में लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल जैसे विभिन्न आर्थिक मापदंडों के संबंध में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की इन्वेंट्रियों में वृद्धि हुई है।

झ. कारणात्मक संबंध

90. ए डी नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित आयातों के अलावा किन्हीं अन्य ज्ञात कारकों की जांच करना जरूरी है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं या क्षति पहुंचा सकते हैं, इसलिए इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति को पाटित आयातों के कारण हुई क्षति नहीं माना जा सकता। चूंकि, वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा है और कारणात्मक संबंध की पहले ही मूल जांच में जांच की गई है, अतः प्राधिकारी द्वारा इसकी जांच की गई है कि क्या अन्य ज्ञात सूचीबद्ध कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है या पहुंचाने की संभावना है। इसकी जांच की गई थी कि क्या ए डी नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग द्वारा झेली जा रही क्षति में योगदान दिया है या योगदान देने की संभावना है।

क. तीसरे देश से आयातों की मात्रा और कीमत

91. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा पर या तो पाटनरोधी शुल्क लागू हैं या वे उच्च कीमतों पर हैं।

ख. मांग में संकुचन और/या खपत के पैटर्न में परिवर्तन

92. पूर्ण क्षति अवधि में संबद्ध वस्तुओं की मांग बढ़ी है। विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए, खपत के पैटर्न में परिवर्तन घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान नहीं दे सकता।

ग. निर्यात निष्पादन

93. आवेदकों ने संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। तथापि, उन्होंने घरेलू प्रचालनों में क्षति की संभावना का दावा किया है। आवेदकों ने घरेलू बिक्रियों के लिए लागत निर्धारण और क्षति सूचना अलग-अलग उपलब्ध कराई है। अतः विचारित क्षति की संभावना निर्यातों के कारण नहीं हो सकती।

घ. प्रौद्योगिकी का परिवर्तन

94. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग को क्षति का कारण होने के रूप में प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के संबंध में कोई मुद्दा नहीं उठाया है।

ड. कंपनी के अन्य उत्पादों का निष्पादन

95. प्राधिकारी ने नोट किया है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा इस आशय का निवेदन नहीं किया है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित और बेचे जा रहे अन्य उत्पाद निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का एक संभव कारण है।

च. व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियां और विदेशी व घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

96. संबद्ध वस्तुओं का आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं है और यह देश में मुक्त रूप से आयात योग्य हैं। घरेलू उत्पादक संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमतों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। घरेलू उद्योग की कीमतें उल्लेखनीय रूप से संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमतों से प्रभावित हैं। इसके अतिरिक्त, किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा यह सुझाव देने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों में कोई परिवर्तन हुआ है।

छ. घरेलू उद्योग की उत्पादकता

97. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता के कारण घरेलू उद्योग को संभव क्षति के संबंध में न तो घरेलू उद्योग द्वारा और न ही किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई अनुरोध किया गया है।

ज. क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना

98. एक पुनरीक्षा जांच में, प्राधिकारी द्वारा यह निर्धारित किया जाना जरूरी है कि क्या संबद्ध वस्तुओं के पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश जारी रहने अथवा प्रवेश किए जाने की संभावना है और यदि शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो क्या इन पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

ज.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

99. घरेलू उद्योग ने पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में निम्नानुसार अनुरोध किया है :-

- i. संबद्ध देशों में उत्पादक भारी क्षमताओं को अनुरक्षित करते हैं।
- ii. अतिरिक्त क्षमताओं के कारण, उत्पादकों ने भी भारी मालसूची संचित की है। इन मालसूचियों की उपस्थिति स्वयं में, पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में भारत को बड़े हुए निर्यातों की भारी संभावना को दर्शाता है।
- iii. संबद्ध देशों से उत्पादकों/निर्यातकों का निर्यात प्रचालन उच्च है। उनके राजस्व का बड़ा भाग निर्यात बिक्रियों से उत्पन्न होता है।
- iv. संबद्ध देशों से उत्पादकों/निर्यातकों के पास उल्लेखनीय अप्रयुक्त क्षमताएं हैं जो भारत में संपूर्ण मांग को आसानी से पूरा कर सकती हैं।
- v. संबद्ध देशों से उत्पादकों/निर्यातकों के पास मुक्त रूप से निस्तारणीय (डिस्पोजेबल) उत्पादन क्षमताएं हैं।
- vi. थाईलैंड में उत्पादकों ने या तो हाल ही में क्षमता में विस्तार आरंभ किया है या विस्तार का प्रस्ताव किया है। थाईलैंड में प्रचुर क्षमताओं के बावजूद विस्तार किया जा रहा है।
- vii. संबद्ध देशों से निर्यातक प्रथमदृष्ट्या पाटित कीमतों पर तीसरे देशों को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात कर रहे हैं।
- viii. चीन में संबद्ध वस्तुओं की मांग में गिरावट आई है।
- ix. निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा दायर प्रश्नावली उत्तर भी स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि पाटन की संभावना और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना है। निर्यातकों द्वारा दायर उत्तर दर्शाते हैं; (1) निर्यातकों के पास अतिरिक्त और अनुप्रयुक्त क्षमताएं; (2) निर्यातकों के पास मुक्त रूप से डिस्पोजेबल क्षमताएं; (3) मालसूचियों में वृद्धि; (4) भारत को निर्यातों की बिक्री कीमत में उल्लेखनीय गिरावट; (5) निर्यात अनुकूलन।
- x. निर्यातकों ने अपने उत्तरों में भारत को निर्यात के अपने अभिप्राय को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि वर्तमान ए डी डी के प्रभाव ने उन्हें अन्य देशों को निर्यात करने के लिए विवश किया है। इसलिए, इसकी बहुत संभावना है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में इन आयातों को भारत में पुनः प्रेषित किया जाए।
- xi. इस अवधि में, घरेलू उद्योग की मांग में चीन जन. गण. में गिरावट आई है। चीन में अतिरिक्त क्षमताओं की उपस्थिति के साथ, चीन में मांग में गिरावट उत्पादकों को अधिक लाभप्रद बाजारों की खोज करने के लिए विवश करेगी।
- xii. पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना मौजूद है।
- xiii. निर्यातकों ने संभावना पर घरेलू उद्योग के दावों का प्रतिवाद करने के लिए कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं कराए हैं।

- xiv. प्रश्नावली उत्तर के भाग 2 के अनुसार, पैनल प्लस एम डी एफ कं० लि० ने जनवरी-दिसंबर, 18 में अपनी क्षमताओं को 76 प्रतिशत तक बढ़ाया है। कंपनी के क्षमता उपयोग में 45 प्रतिशत तक गिरावट आई है। मालसूची में 2018 में 53 प्रतिशत की और जांच की अवधि के दौरान 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। क्षमता उपयोग में 45 प्रतिशत की गिरावट दर्शाती है कि निर्यातक के पास महत्वपूर्ण अनुप्रयुक्त क्षमताएं हैं।
- xv. मालसूचियों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। खतरे के विश्लेषण पैरामीटरों में भी एक में मालसूचियों में वृद्धि हुई है। संभावना को निर्धारित करने के लिए जरूरी किसी अन्य विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। निर्यातक की मालसूचियों में वृद्धि पर्याप्त है।
- xvi. प्रश्नावली का भाग 2 दर्शाता है कि जांच की अवधि में रॉबिन रिसोर्सेज (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी. के क्षमता उपयोग में 39 प्रतिशत की गिरावट आई है जो अप्रयुक्त क्षमताओं में वृद्धि को स्थापित करता है। यदि निर्यातक की घरेलू बिक्रियों में वृद्धि होती है तो इसका अर्थ यह है कि अप्रयुक्त क्षमताएं निर्यातों के लिए अभिप्रेरित हैं। हालांकि, निर्यातक का अनुरोध उत्तर के भाग 2 में उपलब्ध कराई गई सूचना के विपरीत है। निवेदन दर्शाता है कि घरेलू उपग्रहण संतुलित था। तथापि, उत्तर दर्शाता है कि घरेलू बिक्रियों में 9 प्रतिशत की गिरावट आई है।
- xvii. अब जब कि उत्तर देने वाले निर्यातकों ने तीसरे देश की निर्यात कीमत सहित उत्तर दायर किए हैं, संभावना संबंधी विश्लेषण को सूचना की पर्याप्तता और परिशुद्धता के अधीन निर्यात के आंकड़ों पर आधारित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी प्रश्नावली उत्तर तथा निर्यातक कंपनियों के व्यापार आंकड़े, दोनों, से संभावना का निर्धारण कर सकते हैं।
- xviii. जहां तक थाईलैंड के लिए क्षमता और उत्पादन संबंधी आंकड़ों में तोड़-मरोड़ का संबंध है, घरेलू उद्योग ने अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं के अनुसार सूचना उपलब्ध कराई है। उसके अलावा, पी यू सी और एन पी यू सी की क्षमताओं का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। अब जब कि निर्यातक ने अपनी उत्पादन क्षमताओं के संबंध में वास्तविक सूचना उपलब्ध कराई है, तो इस पर सूचना की पर्याप्तता और यथार्थता के आधार पर भरोसा किया जा सकता है।

ख.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

100. पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए अनुरोध निम्नानुसार हैं :-
 - i. इसकी कोई संभावना नहीं है क्योंकि उत्पादकों का ध्यान मुख्य रूप से घरेलू बाजार, मिडिल ईस्ट और एसियान बाजार पर केंद्रित है।
 - ii. थाईलैंड उत्पादकों की क्षमता और उपयोग दरें और उत्पादन संख्या जो याचिका में उपलब्ध कराई गई है, त्रुटिपूर्ण हैं और यह स्पष्ट नहीं है कि दावा सिर्फ पी यू सी के लिए किया गया है या एम डी एफ के लिए। ऐसी कोई अधिशेष क्षमता है नहीं है जो उपायों की अनुपस्थिति में भारत में प्रवेश कर सके। थाई निर्यातकों की चिंता भारत में विद्यमान उपभोक्ता आधार को बनाए रखने की और अत्यधिक परिवर्तनकारी बाजार में उपस्थिति के लाभों से वंचित न रहने की है।
 - iii. कुल क्षमता में से, बहुत से उत्पादक पी यू सी का उत्पादन ही नहीं करते। क्षमताओं को बाजार मांग आदि के अनुसार बदला नहीं जा सकता।
 - iv. इसकी कोई संभावना नहीं है जैसाकि इस तथ्य से देखा जा सकता है कि किसी अन्य देश ने थाई निर्यातों पर ए डी डी लागू नहीं किया है।
 - v. थाई उत्पादकों से प्राप्त सूचना के आधार पर उनकी औसत निर्यात कीमतें, व्यापार के समान स्तर पर और निर्यात की जा रही समान विशिष्टताओं के कारण घरेलू बिक्री कीमतों से लगभग 10 प्रतिशत अधिक हैं।

- vi. क्षमताओं का एक बड़ा भाग पहले ही गैर पी यू सी और मिडिल ईस्ट व एसियान जैसे अन्य बाजारों को समर्पित किया गया है। भारतीय बाजारों को भूत, वर्तमान या भविष्य, कभी भी, थाईलैंड के लिए आधारभूत बाजार के रूप में विचारित नहीं किया गया है।
- vii. एचएस 441113 के मामले में, थाईलैंड से पी यू सी के कुल आयातों का 59 प्रतिशत से अधिक मिडिल ईस्ट के लिए और 15 प्रतिशत एसियान के लिए निर्दिष्ट है। 2015 से 2019 की अवधि में, मिडिल ईस्ट को आयातों में 82,025 मी. टन की वृद्धि हुई है। इन निर्यातों की एक महत्वपूर्ण मात्रा 5 मिमी. से कम मोटाई के लिए है। 2019 में भारत को निर्यात किए गए 12,000 मी. टन का 95 प्रतिशत से अधिक भाग पी यू सी नहीं है।
- viii. भारत को एचएस 441114 के निर्यात 0.3 प्रतिशत से कम है और निर्यात अधिकतर मिडिल ईस्ट और एसियान के लिए निर्दिष्ट है।
- ix. एक समाप्त पुनरीक्षा में विद्यमान पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की स्थितियों को सिद्ध करने के लिए पाटन और क्षति की संभावना पर उपलब्ध कराई गई सूचना सकल रूप से अपर्याप्त और अविश्वसनीय है, जैसाकि नियमावली में अनिवार्य किया गया है। पक्षकारों ने इस संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 का आश्रय लिया है। वादी घरेलू उद्योग को इस समाप्ति के परिणामों को तथ्यों के आधार पर प्रदर्शित करना है न कि केवल अनुमानों, धारणा और अटकलों के आधार पर। शुल्कों को समाप्त किए जाने की स्थिति में कीमतों को कम कर भारत को निर्यात करने की कोई विवशता उनके समक्ष उपस्थित नहीं है।
- x. पाटन और क्षति की संभावना को मापने से प्रासंगिक पैरामीटर स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि थाईलैंड पर शुल्कों को समाप्त करने की स्थिति में पाटन और क्षति का कोई संभावना नहीं है। निर्यातक एक पूरी तरह से स्थापित बाजार में प्रचालन कर रहे हैं और शुल्कों को समाप्त किए जाने से किसी भी तरह से निर्यातकों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। शुल्कों को समाप्त करने की स्थिति में कीमतों में कमी करके भारत को निर्यात करने की कोई विवशता नहीं है।
- xi. याचिका में प्रस्तुत किए गए क्षमता के विवरण, तृतीय देश को निर्यातों से संबंधित विवरण आदि भ्रामक हैं और इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी को वर्तमान और संभावना संबंधी सभी पैरामीटरों के निर्धारण के लिए उत्तरों में उपलब्ध कराए गए डाटा का प्रयोग करना चाहिए।
- xii. शुल्क की समाप्ति की स्थिति में और मूल मामले में ए डी डी को लागू न किए जाने के पश्चात की निर्यातों की प्रवृत्ति में, जैसाकि याचिकाकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया है, भारत में कुछ विशेष प्रयोक्ताओं ने इसके उत्पाद को सर्वाधिक उपयुक्त पाया है और निर्यातकों को ऐसे प्रयोक्ताओं का प्रबंध करने के लिए किसी कीमत विरूपण का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है।
- xiii. अत्यधिक अप्रयुक्त क्षमताओं के दावे सत्य नहीं हैं, क्योंकि पी ओ आई और पी ओ आई पश्चात अवधि में क्षमताएं समान बनी रही हैं जबकि क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है और निर्यातक 90 - 99 प्रतिशत की रेंज में प्रचालन कर रहा है। भारत और तीसरे देशों को निर्यातों में गिरावट के साथ उत्पादन में मामूली वृद्धि हुई है। घरेलू उपग्रहण संतुलित था। आंकड़े दर्शाते हैं कि निर्यातक का क्षमता उपयोग इसके निर्यात बाजार से सीधे संबंधित नहीं था और घरेलू आपूर्ति ही इसका मुख्य भाग है।
- xiv. अत्यधिक अप्रयुक्त क्षमताओं का दावा सत्य नहीं है क्योंकि निर्यातक की क्षमता पी ओ आई और पी ओ आई पश्चात की अवधि में समान बनी रही है और उपयोग 75-85 प्रतिशत के उचित स्तर के बीच बना रहा है। बल्कि संयंत्र स्तर पर वास्तविक उपयोग उत्पाद मिश्र के कारण उच्च बना रहा है।
- xv. संभावना की जांच एक आगे देखने वाला बयान है और घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान पैरामीटरों में उतार-चढ़ाव का संदर्भ दिया है। कंपनी की क्षमता पी ओ आई पश्चात अवधि में भी समान बनी रही है। पैनल प्लस से कोई खतरा नहीं है क्योंकि कंपनी के पास कोई महत्वपूर्ण अतिरिक्त क्षमता आदि मौजूद नहीं है।
- xvi. पक्षकार द्वारा भागीदारी डी आई के गलत दावे का खंडन करने के लिए की गई है और यह नहीं दर्शाती कि भारतीय बाजार निर्यातकों के लिए लाभप्रद है।

- xvii. जारी आयातों से क्षति की अनुपस्थिति वर्तमान शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में भी क्षति की संभावना की अनुपस्थिति की ओर संकेत करती है।
- xviii. रॉबिन रिसोर्सेज से कोई खतरा नहीं है क्योंकि कंपनी के पास कोई महत्वपूर्ण अत्यधिक क्षमता आदि नहीं है और विगत में कंपनी के लिए निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन भी या तो नकारात्मक था या बहुत नगण्य था।
- xix. अत्यधिक क्षमता का अभाव है जिससे घरेलू बाजार की तुलना में प्रमुख निर्यात बाजारों को थाई उत्पादकों की उच्च औसत बिक्री कीमत के संयोजन में, तुलना में भारत को निर्यातों में वृद्धि करने के लिए थाई उद्योग की संभावना कम हो जाएगी।

अ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

101. प्राधिकारी ने धारा 9क (5), नियम 23 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II (vii) की शर्तों में महत्वपूर्ण क्षति के खतरे से संबंधित पैरामीटरों तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकार्ड पर लाए गए अन्य संगत कारकों के तहत निर्धारित अनिवार्यता पर विचार करते हुए क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना की जांच की है। प्राधिकारी ने निम्नानुसार नोट किया है।
102. वर्तमान जांच संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लागू किए गए शुल्कों की निर्णायक समीक्षा है। नियमावली के तहत, यह निर्धारित किए जाने की जरूरत है कि क्या पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने को जारी रखने की आवश्यकता है। इस बात की जांच करने की भी जरूरत है कि क्या लगाया गया शुल्क अभिप्रेरित उद्देश्य को पूरा कर रहा है।
103. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने अन्य संगत कारकों की भी जांच की है जिनका पाटन के जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की संभावना पर असर डाल सकता है। पाटन की पुनरावृत्ति या जारी रहने की संभावना की जांच और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति को जांच निम्नानुसार है :-

i. संबद्ध देशों में उत्पादकों/निर्यातकों की महत्वपूर्ण उत्पादन क्षमता और अतिरिक्त क्षमताओं को अवशोषित करने की अन्य निर्यात बाजारों की क्षमता

104. उत्तर देने वाले निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर का विश्लेषण निम्नानुसार दर्शाता है:-

विवरण	इकाई	रॉबिन रिसोर्सेज (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी. मलेशिया	पैनल प्लस एमडीएफ कं० थाईलैंड
क्षमता	सीबीएम	***	***
संयंत्र उत्पादन	सीबीएम	***	***
क्षमता उपयोग	%	***	***
उत्पादन-पीयूसी	सीबीएम	***	***
घरेलू बिक्रियां	सीबीएम	***	***
भारत को निर्यात	सीबीएम	***	***
अन्य देशों को निर्यात	सीबीएम	***	***

105. संबद्ध देशों से संबंधित क्षमताओं के संबंध में भारतीय उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई और अधिक सूचना निम्नानुसार दर्शाती है :-

उत्पादक	क्षमता (मी. टन)
डीएआरई	11,25,000
गुआंगडांग वेहुआ	10,12,500
वानाचाई ग्रुप पब्लिक कंपनी लि०, थाईलैंड	8,77,500
पैनल प्लस थाईलैंड	5,02,500

ग्रीन पैनल प्रोडक्ट्स	3,75,000
मेट्रो एमडीएफ कं० लि०	3,75,000
एडवांस फाइबर कं० लि०	3,37,500
गुआंगझोऊ हौफेंगझोऊ वुड कं० लि०	2,62,500
मै० डांगहवा ग्लोबल सेल्स एसडीएन. बीएचडी., मलेशिया	2,70,000
एमडीएफ कं० लि०	1,92,750
एस. किज्वाई इंटरप्राइजेस कं० लि०	2,10,000
डैकेन ग्रुप	1,72,500
वाइजवुड्स	1,80,000
मै० मेरबॉक एमडीएफ लंका (प्रा०) लि०, श्रीलंका	1,35,000
मै० रॉबिन रिसोर्सेज (मलेशिया) एसडीएच. बीएचडी. मलेशिया	1,46,250
एस.पी.बी.पी. पैनल इंडस्ट्रीज कं० लि०	1,50,000
मै० डांगहवा एमडीएफ (एम) एसडीएच. बीएचडी., मलेशिया	97,500
योगलिन ग्रुप	90,000
मैगना फोरमोस्ट	75,000
युनफु झेनयिंग वुड कं० लि०	78,750
संगामत पैनल बोर्ड एसडीएच. बीएचडी.	60,000

106. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा आवेदन में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में दर्शाई गई क्षमता भारत में मांग की बहुत अधिक विदेशी उत्पादकों की क्षमताओं को दर्शाती है।

i. मालसूची में वृद्धि

107. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातकों से उत्तर दर्शाते हैं कि उत्तर देने वाले निर्यातकों के पास मालसूचियों में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों में उत्पादक निर्यातोन्मुखी हैं। पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में, यह संभावना है कि संबद्ध देश भारत को अपने निर्यातों में वृद्धि करेंगे।

ii. तृतीय देश पाटन और क्षति

108. निम्नलिखित निर्यातकों ने निर्णायक समीक्षा जांच के लिए संगत प्रश्नावली उत्तर सहित, निर्धारित स्वरूप और तरीके में प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत किए हैं। इसलिए, प्राधिकारी ने प्रश्नावली उत्तर की जांच की है और सामान्य मूल्य (अर्थात् पाटित) और क्षति कारक (अर्थात् घरेलू उद्योग के एन आई पी से निम्न) से कम कीमतों पर तीसरे देशों को इन निर्यातों द्वारा निर्यातों की मात्रा अभिनिश्चित की है :-

i. पैनल प्लस एमडीएफ कं० लि०

ii. रॉबिन रिसोर्सेज (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी.

109. नीचे दी गई सारणी पाटित, आकर्षक और क्षति कारक कीमतों पर तीसरे देशों को इन निर्यातकों द्वारा निर्यातों की मात्रा को दर्शाती है।

जांच की अवधि – रॉबिन रिसोर्सेज (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी –मलेशिया

	भारत को निर्यात सीबीएम	तीसरे देश को निर्यात सीबीएम	कुल सीबीएम
एनआईपी से कम मात्रा	***	***	***
एनआईपी से अधिक मात्रा	***	***	***

सामान्य मूल्य से कम मात्रा	***	***	***
सामान्य मूल्य से अधिक मात्रा	***	***	***
भारत में मांग	***	***	***
मांग के संबंध में %	***	***	***
% में सामान्य मूल्य से कम मात्रा (अर्थात् पाटित)	***	***	***
% के एनआईपी से कम मात्रा (अर्थात् क्षति कारक)	***	***	***

जांच की अवधि – पैनल प्लस एमडीएफ कं. लि. थाईलैंड

	भारत को निर्यात सीबीएम	तीसरे देश को निर्यात सीबीएम	कुल सीबीएम
एनआईपी से कम मात्रा	***	***	***
एनआईपी से अधिक मात्रा	***	***	***
सामान्य मूल्य से कम मात्रा	***	***	***
सामान्य मूल्य से अधिक मात्रा	***	***	***
भारत में मांग	***	***	***
मांग के संबंध में %	***	***	***
% में सामान्य मूल्य से कम मात्रा (अर्थात् पाटित)	***	***	***
% के एनआईपी से कम मात्रा (अर्थात् क्षति कारक)	***	***	***

110. यह देखा जाता है कि रॉबिन रिसोर्सेस और पैनल प्लस द्वारा विश्व के शेष देशों को सामान्य मूल्य और एनआईपी से कम कीमत पर निर्यातों की मात्रा बहुत अधिक है। यह नोट किया जाता है कि जबकि रॉबिन रिसोर्सेस द्वारा भारत को निर्यात गई मात्रा इसके वैश्विक निर्यात का *** प्रतिशत था, इसके उत्पादन का *** प्रतिशत और इसकी क्षमता का *** प्रतिशत था, पैनल प्लस द्वारा भारत को निर्यात इसके वैश्विक निर्यातों का केवल *** प्रतिशत, इनके उत्पादन का *** प्रतिशत और इसकी क्षमता का *** प्रतिशत था। यह भी नोट किया जाता है कि रॉबिन रिसोर्सेस द्वारा भारत को निर्यातों की मात्रा मलेशिया से आयातों का *** प्रतिशत था।

111. यह देखा जाता है कि पैनल प्लस द्वारा भारत को निर्यातों की मात्रा थाईलैंड से आयातों का *** प्रतिशत और विभिन्न स्रोतों से आयातों का *** प्रतिशत था। जांच की अवधि के दौरान मलेशिया और थाईलैंड से आयात जांच की अवधि के दौरान भारत में इन आयातों का *** प्रतिशत और *** प्रतिशत था। इसके अलावा, भारत को पैनल प्लस के निर्यातों की मात्रा बहुत अधिक है।

ट. क्षति और क्षति मार्जिन की मात्रा

112. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद की एन आई पी को जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/डाटा को अपना कर निर्धारित किया गया है। घरेलू उद्योग के लिए एन आई पी को तैयार किया गया है और इस पर क्षति मार्जिन के परिकलन के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना के लिए विचार किया गया है। एन आई पी का निर्धारण करने के लिए, क्षति अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्रियों के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। युटीलिटीज के साथ भी यही उपचार किया गया है। क्षति अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। सर्वोत्तम

क्षमता उपयोग पर विचार करते हुए पी ओ आई में ईष्टतम उत्पादन की संभावना की गई है और प्रति इकाई निर्धारित लागत पर पहुंचने के लिए समान उत्पादन पर विचार किया गया है। उत्पादन लागत पर कोई असाधारण या गैर-आवर्ती व्यय प्रभावित नहीं किए गए हैं। जैसा कि अनुबंध-III में निर्धारित किया गया है और अनुसरण किया जा रहा है, एन आई पी पर पहुंचने के लिए कर पूर्व लाभ के रूप में विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात् औसत निवल निर्धारित परिसंपत्तियां एवं औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित आय (कर पूर्व @ 22 प्रतिशत) की अनुमति दी गई थी। क्षति मार्जिन को निर्धारित करने के लिए इस प्रकार निर्धारित क्षतिरहित कीमत की संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत के साथ तुलना की गई है।

113. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं की क्षतिरहित कीमत, संबद्ध देशों से निर्यातों के पहुंच मूल्य के साथ तुलना किए जाने पर पी ओ आई के दौरान निम्नलिखित क्षति मार्जिन दर्शाती है :-

क्र. सं.	उत्पादक	एनआईपी रू./सीबीएम	पहुंच मूल्य रू./सीबीएम	क्षति मार्जिन रू./सीबीएम	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन रेंज
1.	पैनेल प्लस एमडीएफ कं० लि०, थाईलैंड	***	***	***	***	ऋणात्मक
2.	थाईलैंड से असहयोगी उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	0-10
3	रॉबिन रिसोर्सेज (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी., मलेशिया	***	***	***	***	10-20
4	मलेशिया से असहयोगी उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	40-50
5	चीन जन. गण. से सभी उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	(15-25)
6	श्रीलंका से सभी उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	10-20

पाटन और क्षति की संभावना के संबंध में निष्कर्ष

114. रिकॉर्ड पर साक्ष्य यह दर्शाता है कि संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों की मात्रा में स्वतंत्र रूप से वृद्धि हुई है। इन आयातों के कारण जांच की अवधि में घरेलू कीमतों में कटौती हो रही है और घरेलू उद्योग को घरेलू बिक्री कीमतों पर न्यूनकारी प्रभाव के कारण हानि हो रही है। घरेलू उद्योग का समग्र कार्य-निष्पादन में जांच की अवधि में विभिन्न आर्थिक मानदंडों जैसे क्षमता का उपयोग, लाभ, नकद लाभ और आरओआई के मामले में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के पास मालसूची में वृद्धि हुई है। रिकॉर्ड पर सूचना यह दर्शाती है कि संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास क्षमताएं भारत में घरेलू मांग की तुलना में बहुत अधिक है और संबद्ध देशों के पास बहुत अधिक अतिरिक्त क्षमताएं हैं। निर्यातकों की प्रभावली का उत्तर तीसरे देशों को पाटित और क्षतिकारक कीमतों पर इन निर्यातों की अधिक मात्रा को दर्शाता है। इस प्रकार, ये सभी मानदंड सूचित करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में, संबद्ध देशों में निर्यातक पाटित कीमतों पर भारत में इस उत्पाद का और अधिक निर्यात करेंगे जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होगी।

ठ. प्रकटीकरण पश्चात टिप्पणियां

115. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रकटन विवरण के उत्तर में इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकांश अनुरोध पुनरावृत्तिक प्रकृति के हैं और हितबद्ध पक्षकारों ने अधिकांशतः अपने पूर्व के अनुरोधों जिनकी पहले ही प्राधिकारी द्वारा जांच और इस पर चर्चा की जा चुकी है, को दोहराया है। घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन विवरण के संबंध में निम्नलिखित नए अनुरोध किए गए हैं।

ठ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

116. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन विवरण के संबंध में किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- i. प्राधिकारी द्वारा पूर्व की जांचों में अपनाई गई पद्धति लागू रहेगी यदि हितबद्ध पक्षकार उससे अलग हटने की आवश्यकता सिद्ध नहीं करते हैं। पीसीएन को अपनाने के संबंध में तथ्य नए तथ्य नहीं हैं। प्राधिकारी ने पूर्व की जांचों में पीसीएन को नहीं अपनाया था।
- ii. प्राधिकारी ने एडवांस फाइबर कं. लि., थाईलैंड और वाइसवुड्स कं. लि., थाईलैंड द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों को सही तरीके से अस्वीकार किया है क्योंकि उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों में बहुत अधिक खामियां थीं।
- iii. आयातों में वृद्धि पाटनरोधी शुल्क के मौजूद रहने के बावजूद है।
- iv. मालसूची में वृद्धि आदर्शतम से कम कीमतों पर संबद्ध वस्तु देने के बावजूद है।
- v. पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त किए जाने की स्थिति में, याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर आगे प्रभाव पड़ेगा।
- vi. पैनल प्लस की नकारात्मक भारित औसत क्षति मार्जिन पैनल प्लस के लिए संभावना नहीं होने के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है। पैनल प्लस द्वारा किए गए बहुत अधिक निर्यात एनआईपी से कम कीमतों पर हुए हैं।
- vii. भारित औसत के आधार पर नकारात्मक क्षति मार्जिन संभावना की अनुपस्थिति के संबंध में निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है। उपलब्ध सूचना भारत को निर्यात कीमत की तुलना में वास्तविक रूप से अधिक के रूप में तीसरे देशों को निर्यात कीमत नहीं दर्शाती है। कोठारी शुगर्स ऐंड केमिकल्स बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी का संदर्भ लिया गया है, एनआईपी से कम कीमत पर लेन-देन पर क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए विचार दिए जाने की अनुमति दी गई थी जिसका संदर्भ होनेस्ट इंटरप्राइजेज लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में भी लिया गया था।
- viii. शुल्क के विस्तार की सिफारिश जांच की अवधि में नकारात्मक क्षति मार्जिन के बाद भी पिछले मामलों में की गई है और इस कारण से केवल नकारात्मक क्षति मार्जिन के कारण निर्यातक पर शुल्क को वापस लिए जाने का कोई औचित्य नहीं है।
- ix. वर्तमान जांच में औसत क्षति मार्जिन भ्रमित करने वाला है और शुल्क को पैनल प्लस पर बढ़ाए जाने की आवश्यकता है क्योंकि पैनल प्लस द्वारा क्षतिकारक आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।
- x. प्राधिकारी द्वारा मानी गई क्षतिकारक कीमत निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना में अलग स्तर पर है। समायोजन दोनों को एक स्तर पर लाने के लिए या तो निवल बिक्री प्राप्त अथवा क्षतिकारक कीमत के संबंध में किया जाना है।
- xi. संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण घरेलू उद्योग को सतत पाटन और क्षति हुई है। पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति की पर्याप्त संभावना भी मौजूद है।
- xii. पाटनरोधी शुल्कों का विस्तार जनहित के विरुद्ध नहीं होगा क्योंकि घरेलू उद्योग ने क्षमताओं में वृद्धि की है और यह देश में कुल मांग को पूरा करने में सक्षम है। भारत आत्म-निर्भर बन गया है।
- xiii. पाटन कानून का उद्देश्य एक समान अवसर स्थापित करना तथा भारतीय उद्योग के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की अनुमति देना है। यह आयातों को नहीं रोकेगा अथवा उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करेगा।
- xiv. हितबद्ध पक्षकार थाईलैंड और मलेशिया के उत्पादक हैं जो सहज रूप से केवल अपने निजी हितों और न कि भारत के हितों के प्रति चिंतित हैं। किसी भी उपभोक्ता ने शुल्क के विस्तार के विरुद्ध चिंताएं व्यक्त नहीं की हैं।

ठ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

117. प्रकटन विवरण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध नीचे दिए गए अनुसार हैं:

- i. वाइजवुड्स कंपनी ने वर्तमान जांच में पूर्ण रूप से सहयोग किया है और सभी दस्तावेज एवं आंकड़े सही रूप से दिए हैं।
- ii. वाइजवुड्स का व्यापार क्रियाकलाप भारत को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है और इस कारण से उन कंपनियों जिन्होंने इस जांच में सहयोग नहीं किया है, के साथ शुल्क की दर को मिलाने के बजाए अलग-अलग शुल्क निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है।
- iii. प्राधिकारी द्वारा पैरा 17 में पाटन और क्षति के मार्जिन के निर्धारण के लिए पीसीएन पद्धति के संबंध में प्राधिकारी द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के बारे में यह अनुरोध किया जाता है कि वर्तमान मामले में इस दावे के गुण को देखे बिना विगत परिपाटी को अपनाना न्यायोचित नहीं है। सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार तुलनीय उत्पाद प्रकार पर विचार करते हुए किया है और इस प्रकार की तुलना पाटनरोधी करार के अंतर्गत तथा भारतीय पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत भी एक मौलिक अपेक्षा है। यहां कंपनी ने बहुत अधिक अंतरों को दर्शाते हुए ऐसे प्रकारों के अलग-अलग लागत और कीमत ब्यौरे दिए हैं जो अकेले पाटन और क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए पीसीएन से पीसीएन तुलना को सही ठहराता है।
- iv. मामूली 47 प्रतिशत आधार का निर्माण करने के लिए पर्याप्त प्रतिशत नहीं है क्योंकि इतनी कम मात्रा रखने वाले याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए क्षति संबंधी दावे को भारतीय उत्पादकों द्वारा हानि उठाई गई क्षति के प्रतिनिधिक के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- v. पाटन मार्जिन जिसे प्रकटन में निर्धारित किया गया है, सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की अनुपयुक्त तुलना का परिणाम है और समान प्रकारों की तुलना कर ऐसे क्षति मार्जिन का निष्पक्ष निर्धारण शून्य अथवा बहुत मामूली पाटन मार्जिन देगा।
- vi. याचिकाकर्ता को संबद्ध देशों से कुछ आयातों के कारण कोई प्रतिकूल प्रभाव का सामना नहीं करना पड़ा। प्राधिकारी को इससे बड़े तथ्य को नोट करना चाहिए कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं पर शुल्क कुछ समय से लागू रहे हैं और संबद्ध देशों से आयात जांच की अवधि के दौरान भारतीय मांग का केवल लगभग 6 प्रतिशत था जो आयात का कोई खतरनाक स्तर नहीं है। न ही ऐसे आयात के संबंध में यह माना जा सकता है कि इसके कारण वर्तमान शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में याचिकाकर्ता को क्षति का कोई खतरा है।
- vii. घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में मात्रा के मानदंडों के मामले में कई गुना वृद्धि हुई है। मात्रा में कोई क्षति नहीं है। घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में लाभप्रदता में कुछ गिरावट का दावा किया है। इस संबंध में यह नोट किया जा सकता है कि संबद्ध देशों से आयातों के कारण किसी भी रूप में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ रहा था और वे अन्य देशों से हो रहे आयात की उच्चतर मात्रा थी। लाभप्रदता में गिरावट प्रयोक्ता उद्योगों में डाउनटाइम का परिणाम रहा है जिसका आयातों से कोई लेना-देना नहीं था। क्षति की जांच ऐसे व्यापक आर्थिक वास्तविकताओं को देखते हुए और न कि संकीर्ण प्रिज्म पर नहीं किया जा सकती है ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि क्षति हुई है। यदि कीमत में कटौती/कम कीमत पर बिक्री/हास के दावे सही होते तब घरेलू उद्योग बिक्री में वृद्धि नहीं की होती। कीमत का निर्धारण स्पष्ट रूप से स्वदेशी कारकों और न कि संबद्ध देशों से आयातों से किसी कथित अनुचित प्रतिस्पर्धा के कारण प्रभावित हुआ था।
- viii. प्रकटन विवरण में शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में अधिक आयात होने की संभावना के संबंध में की गई टिप्पणी को नहीं माना जाता है। चूंकि प्राधिकारी ने पैरा 104 में दी गई तालिका को छोड़कर सूचीबद्ध रूप में भी विचाराधीन सूचना प्रकट नहीं की है, पक्षकार किसी सार्थक टिप्पणियों को देने की स्थिति में नहीं हैं और संभावना पर किए गए इसके पूर्व के अनुरोधों को दोहराते हैं।

- ix. यह टिप्पणी कि संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास क्षमताएं भारत में घरेलू मांग से बहुत अधिक है, शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में पाटन और क्षति की किसी संभावना को सूचित नहीं करता है। भारत में मांग की क्षमता की तुलना में संबद्ध देशों में क्षमता दर्शाना मात्र संभावना की जांच का कोई मानदंड नहीं है। यह दर्शाया जाना चाहिए कि ऐसी सभी क्षमताएं अधिक और निष्क्रिय क्षमताएं हैं और ये भारत के लिए सक्रिय किए जाने के लिए भारत में शुल्क के समाप्त होने का इंतजार कर रहे हैं। यदि यह संभावना इतनी अधिक होती तब जांच की अवधि में भी आयात बहुत अधिक और क्षतिकारक तथा अपेक्षाकृत अधिक पाटित दर पर हुआ होता।
- x. संभावना के संबंध में दी गई क्षति संबंधी आंकड़े और सीमित सूचना यह दर्शाती है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना नहीं है।
- xi. इन शुल्कों ने वर्तमान मामले में अपने सभी अभीष्ट उद्देश्यों को पूरा किया है और वर्तमान मामला मौजूदा शुल्कों को जारी नहीं रखने की सिफारिश करने के लिए एक उपयुक्त मामला है और हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं।
- xii. थाई के निर्यातकों के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।
- xiii. शुल्क की दर पर एडवांस फाइबर कंपनी लि. के लिए विशिष्ट रूप से विचार किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने इस जांच में सहयोग किया है।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

118. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकांश अनुरोध पुनरावृत्तिक प्रकृति के हैं। इन अनुरोधों की जांच पहले ही इस जांच परिणाम में उपयुक्त स्थानों पर की गई है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के अतिरिक्त/नए संगत अनुरोधों की जांच नीचे दिए गए अनुसार की है:
 - क. घरेलू उद्योग को क्षति के नहीं होने के संबंध में उसकी समुचित रूप से जांच की गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे वर्तमान और संभावित दोनों क्षति पर विचार करें।
 - ख. पीसीएन वार विश्लेषण के संबंध में यह दोहराया जाता है कि उसी मुद्दे पर प्राधिकारी द्वारा उसी उत्पाद के लिए पाटनरोधी शुल्क की जांच के मामले में पूर्व में चर्चा की गई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि इस आधार पर पीसीएन पद्धति को नहीं अपनाया जाए। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई औचित्य नहीं दिया गया है जो पूर्व की जांच परिणामों से अलग हटने की आवश्यकता को सही बताता हो।
 - ग. पीसीएन वार विश्लेषण के मामले में पाटन के नहीं होने की संभावना के बारे में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और इस कारण से यदि कोई वर्तमान पाटन नहीं भी था तब निर्यातक से यह अपेक्षित है कि वे पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में पाटन और क्षति की संभावना का नहीं होना सिद्ध करें।
 - घ. प्राधिकारी से हितबद्ध पक्षकारों की कमियों के संबंध में पत्र के बारे में यह नोट किया जाता है कि कमियों को दूर करने के अवसर का उपयोग हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रश्नावली का उत्तर पूरा करने और कुछ नई सूचना जिसे प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करते समय नहीं दिया गया था, उपलब्ध कराने के लिए नहीं किया जा सकता है।
 - ड. संभावना की जांच के संबंध में यह नोट किया जाता है कि संभावना का निर्धारण उत्तर देने वाले निर्यातकों के पास क्षमताओं तक सीमित नहीं है। यहां दिए गए संगत पैराओं में सूचीबद्ध सभी कारक संचयी रूप से यह दर्शाते हैं कि पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में संबद्ध देशों में निर्यातक पाटित कीमतों पर भारत को इस उत्पाद का निर्यात और अधिक करेंगे जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होगी।

- च. संभावना संबंधी सूचना के प्रकटन के संबंध में तर्क के बारे में, यह नोट किया जाता है कि यह सूचना निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों के आधार पर है। चूंकि यह सूचना केवल एक वर्ष के लिए है अतः उसे सूचीबद्ध रूप में नहीं दिया जा सकता है।
- छ. पैनल पल्स के भारत और अमेरिका के बीच के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क के लागू रहने के बावजूद यह कंपनी भारत में इस उत्पाद का पाटन कर रहा है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा उपयोग न की गई क्षमताओं, तीसरे देशों को निर्यात, तीसरे देशों को पाटन और क्षतिकारक निर्यात के संबंध में दी गई सूचना स्पष्ट रूप से पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में पाटन और क्षति की संभावना को दर्शाती है। भारत को पैनल पल्स द्वारा वर्तमान निर्यातों की मात्रा भारत में सतत, वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों को इसका निर्यात, इसका उत्पादन और संस्थापित क्षमताओं पर विचार करते हुए बहुत अधिक है। ये मानदंड सामूहिक रूप से सिद्ध करते हैं कि वर्तमान क्षति मार्जिन पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में निर्यातक के संभावित व्यवहार का प्रतिनिधिक नहीं है।
- ज. प्राधिकारी ने विभिन्न सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा भारत को निर्यात की मात्रा पर भी विचार किया है। यह नोट किया जाता है कि रॉबिन रिसोर्सेस पर पाटनरोधी शुल्क की मात्रा प्रति सीबीएम 5.72 यूएस डालर था। भारत को निर्यातों की मात्रा में अन्य देशों को इसके निर्यातों और मलेशिया से भारत में विचाराधीन उत्पाद के उन आयातों की तुलना में भी काफी हद तक वृद्धि हुई। इसके अलावा, पैनल पल्स पर पाटनरोधी शुल्क की मात्रा बहुत अधिक (प्रति सीबीएम 45.27 यूएस डालर) थी और तदनुसार भारत को निर्यातों की इसकी मात्रा विभिन्न देशों को इसके निर्यातों और थाईलैंड से भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में भी बिल्कुल कम है। इसके अलावा, सामान्य मूल्य और एनआईपी से कम कीमतों पर तीसरे देशों को रॉबिन रिसोर्सेस और पैनल पल्स, दोनों के निर्यातों की मात्रा भारत में खपत पर विचार करते हुए बहुत अधिक है, यह दर्शाता है कि पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में संबंधित देशों में निर्यातक संभवतः पाटन कीमतों पर भारत में इस उत्पाद का निर्यात और अधिक मात्रा में करेंगे जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होगी।

ड. भारतीय उद्योग का हित

119. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सामान्य तौर पर पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य घरेलू उद्योग को पाटन की अनुचित व्यापार कार्य-पद्धतियों के द्वारा हुई क्षति को समाप्त करना है जिससे भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से किसी भी प्रकार से संबंधित देशों से आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा और इस कारण से उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
120. यह नोट किया जाता है कि भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में पाटनरोधी शुल्क विशेष रूप से यदि पाटनरोधी शुल्क की लेवी घरेलू उद्योग को क्षति का निवारण करने के लिए आवश्यक सीमा तक सीमित हो, तब कम नहीं होगी। इसके विपरीत पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से पाटन की परिपाटियों के द्वारा प्राप्त किए गए अनुचित लाभ समाप्त हो जाएंगे, घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट रुक जाएगी और संबंधित वस्तुओं के उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

ढ. निष्कर्ष

121. प्राधिकारी के समक्ष दिए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना और किए गए अनुरोधों और उपलब्ध तथ्यों जिसे उपर्युक्त जांच परिणामों में रिकॉर्ड किया गया है, पर विचार करते हुए तथा घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना का उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि:
- क. चीन को छोड़कर संबंधित देशों से संबंधित वस्तुओं का निरंतर पाटन हुआ है। चीन को छोड़कर ये आयात शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में पाटन कीमतों पर भारतीय बाजार में होने की संभावना है।
- ख. घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति हुई है।

- ग. रिकॉर्ड पर सूचना उस स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने की संभावना को दर्शाता है यदि लागू पाटनरोधी शुल्क को समाप्त होने दिया जाता है।
- घ. कीमत में सकारात्मक कटौती, मांग से अधिक क्षमताएं तथा तीसरे देशों को सामान्य मूल्य और क्षति रहित कीमत से कम कीमत पर निर्यातों की बहुत अधिक मात्रा जैसे कारक सामूहिक रूप से थाईलैंड, मलेशिया और श्रीलंका से आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क को समाप्त होने दिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति की संभावना सिद्ध करते हैं।

ज. सिफारिशें

122. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रर्याप्त अवसर दिया गया था ताकि वे पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सूचना उपलब्ध करा सकें।
123. इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त होने दिया जाता है तब पाटन और क्षति के जारी रहने की संभावना है, प्राधिकारी का यह मत है कि शुल्क को जारी रखना चीन जन.गण. को छोड़कर संबद्ध देशों से पीयूसी के आयात पर अपेक्षित है। प्राधिकारी ने शुल्क की मात्रा की जांच की है जिसकी सिफारिश की जानी चाहिए। प्राधिकारी ने भारत और विश्व के शेष देशों को सहयोगी निर्यातकों से पाटित और क्षतिकारक निर्यातों की मात्रा पर विचार किया। प्राधिकारी इसे उपयुक्त मानते हैं कि रॉबिन रिसोर्सेस को छोड़कर सभी निर्यातकों/उत्पादकों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की मौजूदा मात्रा को जारी रखने की सिफारिश की जाए। हालांकि, रॉबिन रिसोर्सेस के मामले में वर्तमान जांच में पाई गई पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन पर विचार करते हुए पाटनरोधी शुल्क की मात्रा में संशोधन करना उपयुक्त होगा। इसके अलावा इस निर्णायक समीक्षा जांच में इन असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों को असहयोग का पुरस्कार नहीं देने की सतत् परिपाटी के अनुसार वर्तमान में यथा-लागू शेष शुल्क दिया जाना अपेक्षित है। तदनुसार, संबद्ध देशों से उत्तर देने वाले उत्पादकों और असहयोगी उत्पादकों के लिए पाटनरोधी शुल्कों की सिफारिश नीचे दी गई शुल्क तालिका के अनुसार की जाती है। इस प्रकार, प्राधिकारी नीचे दी गई शुल्क तालिका में कॉलम 7 के अनुसार मलेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका से कॉलम 3 में उल्लिखित संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर यथा-संशोधित निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को आगे पांच वर्षों की अवधि के लिए लगाए जाने की सिफारिश करना आवश्यक मानते हैं।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष	विवरण	उद्गम का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	यूनिट	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	4411	6 एमएम और उससे अधिक के प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड	थाईलैंड	थाईलैंड सहित कोई देश	पैनल प्लस एमडीएफ कंपनी लिमिटेड	45.27	घन मीटर	यूएसडॉलर
2.	-वही-	-वही-	थाईलैंड	थाईलैंड सहित कोई देश	ऊपर क्र.सं. 1 में उल्लिखित उत्पादक को छोड़कर कोई उत्पादक	45.27	घन मीटर	यूएसडॉलर
3.	-वही-	-वही-	थाईलैंड को छोड़कर कोई देश	थाईलैंड	कोई भी	45.27	घन मीटर	यूएसडॉलर

4.	-वही-	-वही-	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई देश	रॉबिन रिसोर्सेस (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी.	13.29	घन मीटर	यूएसडॉलर
5.	-वही-	-वही-	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई देश	उपर्युक्त क्रम सं. 5 पर उल्लिखित उत्पादक को छोड़कर कोई उत्पादक	36.10	घन मीटर	यूएसडॉलर
6.	-वही-	-वही-	मलेशिया को छोड़कर कोई देश	मलेशिया	कोई भी	36.10	घन मीटर	यूएसडॉलर
7.	-वही-	-वही-	श्रीलंका	श्रीलंका सहित कोई देश	कोई भी	26.49	घन मीटर	यूएसडॉलर
8.	-वही-	-वही-	श्रीलंका को छोड़कर कोई देश	श्रीलंका	कोई भी	26.49	घन मीटर	यूएसडॉलर

त. आगे की प्रक्रिया

124. इन जांच परिणामों के कारण निकलने वाले केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध अपील इस अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

बी. बी. स्वेन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Directorate General of Trade Remedies)

NOTIFICATION

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 8th January, 2021

Case No. (SSR 05/2020)

Subject : Sunset Review anti-dumping investigation concerning imports of 'Plain Medium Density Fibre Board having thickness of 6mm or more' originating in or exported from China PR, Malaysia, Thailand and Sri Lanka.

F. No. 7/6/2020-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as 'the Rules' or 'AD Rules') thereof;

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. The Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) initiated an anti-dumping investigation in respect of imports of Plain Medium Density Fibre Board having thickness of 6mm or more (hereinafter also referred to as "subject goods" or "PUC" or "Product Under Consideration") originating in or exported from China PR, Malaysia, Thailand and Sri Lanka (hereinafter referred to as the "subject countries") on 6th June, 2008 and preliminary anti-dumping duty was recommended vide

Preliminary Findings Notification No. 14/12/2007 dated 2nd February, 2009. On the basis of recommendations made by the Authority in the preliminary findings, provisional anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Notification No. 21/2009 – Customs (ADD) dated 27th February, 2009. Thereafter, the Authority issued Final Findings recommending imposition of definitive anti-dumping duty vide Final Findings Notification No. 14/12/2007 – DGAD dated 26th August, 2009. On the basis of recommendations made by the Authority in the Final Findings, the Central Government imposed definitive anti-dumping duty vide Notification No. 116/2009 – Customs (ADD) dated 8th October, 2009. Thereafter, a Sunset Review (SSR) investigation was initiated by the Authority in respect of imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries vide Notification No. 15/28/2013-DGAD dated 18th February, 2014. The Authority vide Final Findings Notification No. 15/28/2013-DGAD dated 17th August, 2015 concluded that the expiry of anti-dumping duty would lead to continuation or recurrence of dumping and consequent injury and recommended continued imposition of the anti-dumping duty. On the basis of recommendations made by the Authority in the final findings, The Central Government imposed duties vide Notification No. 48/2015-Customs (ADD) dated 21st October, 2015.

2. In terms of Section 9A (5) of the Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

3. Rule 23(1B) of the Rules provides as follows:

“...any definitive anti-dumping duty levied under the Act, shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the Designated Authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.”

4. M/s Greenply Industries Limited / Greenpanel Industries Limited, Century Plyboards (India) Ltd. and Rushil Décor Limited (hereinafter referred to as ‘applicants’ or ‘domestic industry’) filed a duly substantiated application on behalf of the domestic industry before the Authority, in accordance with the Act and the Rules alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and consequent injury to the domestic industry and have requested for review and continuation of the anti-dumping duties, applicable on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.
5. Based on the substantiated application with prima facie evidence of likelihood of dumping and injury filed on behalf of the domestic industry in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority initiated the sunset review investigation vide Notification No. F. No. 7/6/2020-DGTR (SSR No. 05/2020) dated 28th February, 2020 to review the need for continued imposition of the anti-dumping duty in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of the said duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
6. In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act and in pursuance of Rule 23 of the Anti-Dumping Rules, the Central Government vide Notification No. 30/2020 – Customs (ADD) dated 13th October, 2020 extended the Anti-dumping duties till 20th January, 2021.
7. The scope of the present review covers all aspects of the previous investigations concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

B. PROCEDURE

8. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
 - i. The Authority notified the embassy of the subject countries in India about the receipt of the present application before proceeding to initiate the investigations in accordance with sub-rule 5(5) of the AD Rules.

- ii. The Authority issued a Notification dated 28th February, 2020, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating investigation concerning imports of the subject goods from the subject countries.
- iii. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassy of the subject countries in India, known producers/exporters from the subject countries, known importers/users and the domestic industry as well as other domestic producers as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within 30 days from the receipt of notice in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules.
- iv. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters, known importers and to the embassy of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules.
- v. The Embassy of the subject countries in India was also requested to advise the exporters/producers from the subject countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.
- vi. The Authority sent exporter's questionnaire to the following known producers/ exporters in the subject countries, whose details were made available by the applicants, to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - a. Merbok MDF Lanka Pvt. Limited
 - b. Dongwha Fibreboard Sdn. Bhd.
 - c. Daiken Sarawak Bdh. Sd.
 - d. M/s. Evergreen Fibre Berhad (JB) Sdn. Bhd.
 - e. M/s. Evergreen Fibre Berhad (EFB)
 - f. Robin Resources (Malaysia) Sdn Bhd
 - g. M/s. Segamat Panel Boards Sdn Bhd
 - h. M/s. Advance Fibre Co.
 - i. Khon Kaen MDF Board
 - j. Vanachai Panel Industries Co., Ltd.
 - k. Siam Fibreboard Co Limited
 - l. M/s. Metro Fiber Co. Ltd.
 - m. M/s. Vanachai Group Public Co. Ltd.
 - n. M/s. Metro M.D.F. Co. Ltd.
 - o. Tomrich International Trading Limited
 - p. Nanjing ETAI Trading Co Limited
 - q. Linyi Baideli International Trade Co Ltd.
 - r. Linyi Hongfu Timber Co Limited
 - s. Wenzhou Timber Group Co. Ltd.
 - t. Shouguang Guihe Economic and Trade Co Limited
 - u. Zhanjiang Kingstar Building Material Co Limited
 - v. Guangdong Weihua Holding Co., Ltd.
 - w. Linyi Baideli International Trade Co Ltd.
 - x. Shunlong MDF-board Co. Ltd
 - y. Shanghai Sindo Panel Co. Ltd.
 - z. Shuyang New Concept Wood Co., Ltd.

- vii. The following producers/exporters from the subject countries filed exporter's questionnaire response in prescribed manner.
 - a. Panel Plus MDF Company Limited, Thailand
 - b. Robin Resources (Malaysia) SDN. BHD., Malaysia
- viii. The Authority has rejected exporter's questionnaire response filed by Advance Fibre & Wisewoods as the same was not filed in prescribed manner.
- ix. The Authority forwarded a copy of the Initiation Notification to the following known importers/users/user associations, whose names and addresses were made available to the authority, of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within the time limit prescribed by the Authority in accordance with the Rule 6(4):
 - a. Krishna Plywood Products Private Limited
 - b. Jacsons Veneers And Panels Private Limited
 - c. Label Sales Corporation
 - d. Kalinga Imports & Exports Private Limited
 - e. Srivari Traders
 - f. Victory Plywood Distributors
 - g. Thamarapally Brothers Trading Private Limited
 - h. Mathewsons Exports & Imports Private Limited
 - i. R.J.Metals
 - j. Feroke Boards Limited
- x. However, none of the importers/users/user associations have filed any submissions or questionnaire responses in the present investigation.
- xi. The following exporters/producers have filed legal submissions and/or letters of participation in response to the initiation notification:
 - a. Metro MDF Co. Ltd., Thailand
 - b. Wisewoods Co. Ltd., Thailand
 - c. S.P.B Panel Industries Co. Ltd., Thailand
 - d. Thai Panel Product Industry Club (TPPIC)
- xii. Exporters, foreign producers and other interested parties who have not responded to the Authority, or not supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperating interested parties.
- xiii. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xiv. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties. Whenever they requested inspection of public file and copies of the documents therefrom were provided with the same.
- xv. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present investigation has been considered from 1st April 2018 to 30th September 2019 . The injury investigation period has been considered as the period from 1st April 2015 – 31st March 2016, 1st April 2016 – 31st March 2017, 1st April 2017 – 31st March 2018 and POI.

- xvi. Additional/supplementary information was sought from the applicants and other interested parties to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by the domestic industry and exporters/producers was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the investigation.
- xvii. The Non-Injurious Price (NIP) is based on the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the AD Rules. It has been worked out so as to ascertain whether duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- xviii. Information obtained from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) on transaction-wise import data for the past three years, and the period of investigation has been adopted for determination of volume and value of imports of product concerned in India.
- xix. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing held on 11th November, 2020. All the parties who had attended the oral hearing were provided an opportunity to file written submissions, followed by rejoinders, if any.
- xx. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in these Final Findings.
- xxi. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded these Final Findings on the basis of the facts available.
- xxii. In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide Disclosure Statement dated 28th December, 2020 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in these final findings. The Authority notes that most of the post disclosure submissions made by the interested parties are mere reiteration of their earlier submissions. However, the post disclosure submissions to the extent considered relevant are being examined in these Final Findings.
- xxiii. *** in these final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xxiv. The exchange rate adopted by the Authority during the POI for the subject investigation is 1 US\$= 70.79.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

- 9. The product under consideration for the purpose of present investigation is Plain Medium Density Fibre Board, also known as Plain MDF Board.
- 10. It is a composite wood product made out of wood waste fibres glued together with urea formaldehyde resin or melamine resin by applying heat and pressure. It is widely used for partitions, Modular furniture, cabinets etc, due to its smooth and uniform finish. MDF Board is produced in plain form and lamination is additional processing which is carried out after production of Plain MDF Board.
- 11. The laminated Medium Density Fibre Board (laminated MDF Board) is beyond the scope of product under consideration. The Plain Medium Density Fibre Board below 6MM thickness is excluded from the product scope.
- 12. The product under consideration accordingly is, "Plain Medium Density Fibre Board having thickness of 6 MM or more and are classified under Chapter 4, Custom subheading no. 44111300 and 44111400 of the Customs Tariff Act. However, the subject goods are being imported under other tariff sub-heading i.e. 44111200, 44111292, 44111293 and 44111294 as well.

C.1 Views of the Domestic Industry

13. The domestic industry has submitted as follows with regard to product under consideration and like article:
- Present investigation being a sunset review investigation, product under consideration remains the same as defined in the original as well as previously conducted investigations. Further, no significant development has taken place over the period. Therefore, domestic industry refers to and relies upon the previous investigation with regard to product under consideration and like article. The domestic industry is producing the like article to the product under consideration.
 - As regards the contention of the interested party regarding PCN, the domestic industry has submitted that the issue was raised by some interested party in the previous investigation but the same was not accepted by the Authority. However, if the Authority decides, the domestic industry will provide relevant information.

C.2 Views of the other interested parties

14. The following submissions have been made by other interested parties with regard to the product under consideration and like article:
- Robin manufactures and sells three broad types of products covered in PUC i.e., E0, E1/Carb and E2 based on Formaldehyde Emission and cost and price of these grades vary significantly as is evident from the cost sheets provided. Different grades use different glue and other materials depending on the applicable standards on such grades which results in significant differences in both cost and prices of such grades. PUC covers inter se grades with significant cost and price differences which warrant separate determination of dumping and injury margin for such different grades and therefore Dumping Margin and injury Margin to be determined grade wise.
 - Justification for PCN has been provided in the response that the costs of the PCNs identified vary very significantly due to the differences in the cost of inputs used in such specific grades.
 - Robin Resources' request for a PCN wise analysis justified in view of Article 2.4 of the WTO Anti-Dumping Agreement which mandates fair comparison between export price and normal value and Article 3.6 of the WTO Anti-Dumping Agreement which states that the effect of dumped imports is to be assessed in relation to domestic production of the like product when available data permit separate identification. Data has been provided for determination of dumping margin.
 - The Authority should seek corresponding injury data/NIP from petitioners for determination on injury margin.

C.3 Examination by the Authority

15. The product under consideration in the earlier as well as present investigation resented sunset review is Plain Medium Density Fibreboard having thickness of 6mm or more. In the previous investigation, the product under consideration was defined as under:

"The product under consideration is Plain Medium Density Fibre Board, also known as Plain MDF Board. It is a composite wood product made out of wood waste fibres glued together with urea formaldehyde resin or melamine resin by applying heat and pressure. It is widely used for partitions, Modular furniture, cabinets etc, due to its smooth and uniform finish. MDF Board is produced in plain form and lamination is additional processing which is carried out after production of Plain MDF Board.

The laminated Medium Density Fibre Board (laminated MDF Board) is beyond the scope of product under consideration. The Plain Medium Density Fibre Board below 6MM thickness is excluded from the product scope. The product under consideration accordingly is, "Plain Medium Density Fibre Board having thickness of 6 MM or more."

16. The subject goods produced by the domestic industry and that imported from the subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. In view of the same, the product under consideration produced by the domestic industry is treated as like article to the product under consideration imported from subject countries.

17. As regards the arguments of the interested parties regarding the adoption of PCN in the present investigation, it is noted that same issue was earlier dealt by the Authority in case of ADD investigation for the same product wherein it was decided not to adopt PCN methodology on this basis. There does not seem to be any justification to deviate from the stand taken earlier by the Authority.
18. The present investigation, being a sunset review investigation, the scope of product under consideration remains the same as in the previously conducted investigation. The subject goods are classifiable under Chapter 4 of the Customs Tariff Act, 1975 under sub-headings 44111300 & 44111400. However, the subject goods are being imported under other tariff sub-heading i.e. 44111200, 44111292, 44111293 and 44111294 as well. These custom classifications are indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.

D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

19. Rule 2(b) of the AD rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term, ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers.”

D.1 Views of the Domestic Industry

20. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to standing and scope of the domestic industry:
 - i. The Application for initiation of Sunset Review investigation has been jointly filed by Greenply Industries Limited/ Greenpanel Industries Limited, Century Plyboards (India) Ltd. and Rushil Decor Limited. Under Composite Scheme of Arrangement, Greenply Industries Limited was demerged to Greenpanel Industries Limited. Greenply Industries Limited/ Greenpanel Industries Limited, Century Plyboards (India) Ltd. and Rushil Decor Limited have provided all relevant information with regard to the present investigations.
 - ii. Greenply Industries Limited/ Greenpanel Industries Limited, Century Plyboards (India) Ltd. and Rushil Decor Limited have not imported the subject goods.
 - iii. Greenply Industries Limited/ Greenpanel Industries Limited, Century Plyboards (India) Ltd. and Rushil Decor Limited is not related, either directly or indirectly, to any exporter in the subject country or any importer of the dumped article within the meaning of Rule 2(b).

D.2 Views of other interested parties

21. The following submissions have been made by the exporters/other interested parties with regard to the standing and scope of the domestic industry:
 - i. It is unclear whether the petitioners have standing as no percentage is provided in Annex 2.2 for the production of petitioners compared to domestic industry in general.
 - ii. There are six other Indian producers of the goods under consideration, which are not cooperating as interested parties in the present investigation. It is questionable whether these three Applicants alone constitute the "Domestic Industry". The fact that six other Indian producers do not wish to be involved in this investigation undermines the legitimacy of the injury analysis.

D.3 Examination by the Authority

22. The Application in the present case has been jointly filed by Greenply Industries Limited/ Greenpanel Industries Limited, Century Plyboards (India) Ltd. and Rushil Decor Limited (hereinafter also referred to as applicant companies), accounting for 47% of total Indian production. These applicant companies have provided relevant information as per the prescribed format. The Authority notes that there are six other manufactures of the product under consideration namely M/s Balaji Action Buildwell, M/s Shirdi Industries Limited, M/s Mangalam Timber Products Limited., M/s Pioneer Panel Products, M/s Metro Panels Industries and M/s Ranga Particle Board Industries Limited in India. However, these producers have neither supported nor opposed the present investigation.

23. The applicant companies have not imported the product under consideration during POI. Nor are they related to any producer/exporter of the product under consideration in subject countries or importers of PUC in India.
24. Considering the information on record, the Authority holds that the production of the applicant companies, i.e. Greenply Industries Limited/ Greenpanel Industries Limited, Century Plyboards (India) Ltd. and Rushil Decor Limited account for a major proportion of the domestic production of the like article and the applicants thus are eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules. The application therefore satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1 Submissions by the domestic industry

25. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality –
- i. The exporters and producers have resorted to excessive confidentiality. The non-confidential version of the responses filed do not allow a meaningful understanding of the information claimed confidential.
 - ii. The information kept confidential by the responding interested parties forms an essential part of the exporter questionnaire responses. Due to lack of such vital information in the non-confidential version, the Domestic Industry is unable to offer any meaningful submissions and assist the Authority in identifying discrepancies or misrepresentations in the responses.
 - iii. The exporters have not furnished a sufficient non-confidential version of the appendices. Even indexed information has not been made available to the domestic industry.
 - iv. The exporters have not provided information that is freely available in the public domain.
 - v. Submissions filed by the exporters, Advance Fibre and Wisewoods, are in violation of Rule 7 of the Anti-Dumping Rules. The non-confidential version of the responses contains only the write up and no appendix. Reliance is placed on the case of Argentina – Ceramic Tiles wherein the Panel held that the Authority may rely on the confidential information to make determinations only if the non-confidential versions inform the interested parties and enable them to defend their interests. The domestic industry had also relied upon CESTAT decisions in Essar Steel Ltd vs UOI and H. R. Johnson vs Designated Authority in this regard wherein it was stated that a non-confidential summary is to be furnished and if the information is not susceptible to summary, a statement of reasons is to be provided.
 - vi. For the purpose of transparency, there is an obligation on the authority to require the parties to furnish non-confidential summaries which shall be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information submitted in confidence, and this is an important element incorporated in Rule 7(2) of the Anti-Dumping Rules.
 - vii. The non-confidential version of the responses filed by the exporters are not a replica of the confidential information. This is in violation of the practice and procedure followed by the Authority and Trade Notice 1/2009 dated 25th March 2009, Trade notice 1/2013 dated 28th February 2020
 - viii. If the Designated Authority is of the opinion that confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized form, then the Authority may choose to disregard such information and issue the findings accordingly.
 - ix. There is no questionnaire issued to the domestic industry. The domestic industry has provided detailed non confidential version of the application. Para 1 and Para 8 of the initiation notification establishes that the domestic industry is cooperative.

E.2. Submissions by other interested parties

26. Following submissions have been made by other interested parties with regard to confidentiality-
- i. The non-confidential files do not include copy of the non-confidential questionnaires of the domestic industry that should normally be made available to all interested parties in the defence of their interest.

- ii. The lack of non-confidential summary of questionnaire response pertaining to the domestic industry has impeded Thai producers to adequately exercise their rights of defence in these proceedings and this constitutes a breach of Articles 6.4 and 6.5 of the WTO Anti-Dumping Agreement..
- iii. The investigating Authority has not asked additional information or issued any deficiency letter.
- iv. It is a wrong conclusion on the part of domestic industry that the respondents suppressed information and adopted excessive confidentiality.

E.3 Examination by the Authority

27. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the AD Rules provides as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

28. The Authority made non-confidential version of the information provided by various interested parties available to all interested parties for inspection through the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties. A list of all interested parties was uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file was not accessible physically due to ongoing global pandemic.
29. As regards the submission of non-confidential version of the questionnaire responses of the domestic industry, the Authority notes that no questionnaire is issued to the domestic industry. The domestic industry has filed the application as per the prescribed format.
30. Submissions made by the domestic industry and other opposing interested parties with regard to confidentiality, to the extent considered relevant, were examined by the Authority and addressed accordingly. The Authority notes that the information provided by the interested parties on confidential basis was duly examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1. Submissions by the domestic industry

31. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:
- i. The responding exporters have filed incomplete responses and have failed to furnish many vital information such as list of products sold and the details in the appendixes.
 - ii. The Authorities in Vietnam have initiated an anti-dumping duty investigation on exports of product under consideration from the subject countries, including Malaysia and Thailand.

- iii. The exporters have not co-operated sufficiently in the present investigation. No questionnaire response has been filed by any exporter from Sri Lanka and China PR. Therefore, the exporters from these countries are to be considered non-cooperative.
- iv. As regards the contention of the interested parties that the imports from subject countries cannot be of any adverse effect, it is submitted that the duty is extended by the Authority only when the legal requirements are met. The period for which the duty has been in force is not relevant. It is not for the domestic industry to justify how long it needs protection. It is for the exporter to justify how long he would resort to dumping.
- v. The dumping margin is subject to verification and it is for the Authority to determine. Further, the present investigation being a sunset review investigation, the legal requirement is whether dumping and consequent injury is likely in the event of cessation of Anti-dumping duty. The domestic industry has provided sufficient information on the basis of evidence regarding likelihood of dumping and consequent injury to the domestic industry in the event of cessation of anti-dumping duty.
- vi. The matter regarding imposition of anti-dumping duty on Robin Resources in the original investigation is sub-judice, as admitted by the interested parties. The customs notification imposing Anti-dumping duty has not been withdrawn. Further in the last sunset review, the dumping margin of the responding exporter was more than *de minimis*.

F.2. Submissions by other interested parties

32. Following miscellaneous submissions have been made by other interested parties:

- i. Duties have been in force for more than a decade and facts in the present investigation show that imports from Thailand and Malaysia cannot be of any adverse effect on the domestic industry even on expiry of existing duties.
- ii. Purpose of ADD has been met as is evident from current dumping and injury situation.
- iii. Issue regarding non-termination of original investigation despite negative dumping margin in case of exports by Robin Resources is pending before the Supreme Court. Authority rejected Robin's contention that the first SSR was not applicable since the original investigation was liable to be terminated and injury margin of USD 5.72 CBM was determined. Robin has been deprived of fair legal treatment.
- iv. Robin Resources' dumping margin was negative in the original investigation and very low in the first SSR. The injury margin determined for the company was of no consequence and meaning as the dumping jurisprudence is that any injury on account of dumping alone is addressable under the AD rules. Information pertaining to the current POI to determine dumping in the response will show that the exporter continues to sell to India at a price comparable to its domestic market and dumping is not practiced. History of absence of dumping and negligible dumping margin for the past 10-15 years is a fair ground for expiry of present ADD.
- v. Data regarding exports from Robin Resources show that the exporter did not use or misuse the absence of duty to export more to India. The exports will not go up on expiry of ADD, which is also evident from its past behaviour. It could have exported any volume to India without any duty burden if the allegations of excess capacity, inventory pressure, third country dumping etc. alleged by the petitioner were true. Certain users find Robin's products most suitable and Robin does not resort to price distortion practices to cater to them.
- vi. The present investigation is required to be terminated against Thailand where the evidences indicate neither likelihood of dumping from Thailand nor likelihood of injury to the domestic industry caused by the products exported from Thailand. This will lead to the mutual benefit of all parties involved and the favourable bilateral trade relations between the Republic of India and the Kingdom of Thailand.

F.3 Examination by the Authority

33. The Authority has noted all the arguments and counter-arguments of the interested parties and has examined all the submissions made.
- i. With regard to the issue of continuation of duty raised by the interested parties, it is noted that the recommendation for extension of anti-dumping duty is made only when the requisite legal requirements are met.
 - ii. With regard to the submissions of interested parties regarding adequacy and accuracy of the application, the Authority notes that the application contained all the information relevant for the purpose of initiation of investigation. The Authority only after satisfaction that application contained sufficient prima facie evidence to justify initiation of the investigation decided to initiate the present investigation.

G. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN**G.1. Normal Value**

34. Under Section 9A(1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:

- (i) *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
- (ii) *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*
 - (a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - (b) *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);*

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

G.2 Submissions by the domestic industry

35. The submissions made by the domestic industry with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows:
- i. The applicants have calculated Normal value for Thailand, Malaysia and Sri Lanka on the basis of price reported in Market Research Report by Maia Research.
 - ii. Applicants submitted that the Designated Authority is not required to use Chinese prices or costs for the purpose of determination of normal value unless the Chinese exporters establish that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of the product under consideration.
 - iii. The Applicants have submitted that their domestic price and cost cannot be considered unless the Chinese exporters demonstrate that the costs and domestic prices are appropriate and reasonably reflect the costs and price of the product under consideration.
 - iv. The Designated Authority shall follow Para 1-6 of Annexure I for determination of normal value only if the responding Chinese companies establish that their costs and price information is such that individual normal value and dumping margin can be determined. If the responding Chinese companies are not able to demonstrate that their costs and price information can be adopted, the Designated Authority shall reject the claim of individual dumping margin.
 - v. The applicants consider New Zealand as appropriate third country for determination of normal value for China. The Applicants have calculated normal value for China on the basis of price at which goods have been sold from New Zealand to consumers in Canada.

- vi. Export price is calculated after making various adjustments based on market information and general experience and considering most conservative estimates.
- vii. Dumping margin from subject countries is not only significant, but also substantial.
- viii. The past investigations have established that the Thai producers were dumping the product under consideration in India.
- ix. As regards the Trade Map data, the domestic industry has provided information to the best of its ability.

G.3. Submissions by other interested parties

36. The submissions made by other interested parties with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows:
- i. Exports of the goods under consideration to India during the POI is around 500-800 MT with export prices well above normal value.
 - ii. Dumping margin should be calculated grade wise based on the separate cost sheet and price for all three grades submitted by Robin Resources (Malaysia) SDN BHD
 - iii. The Dumping margin claimed in the data based on average price is misleading as it shows third country exports of 70122 MT out of which 23911MT (35%) is claimed as having the potential of triggering positive dumping margin if diverted to India. PCN wise data provided in responses will show that exports if diverted will not create any such dumping effects. Even the 23911MT claimed as having the potential of dumping effect is very low volume compared to Indian demand and even such volumes will not have any adverse effect on the Indian market.
 - iv. Dumping margin for Thailand and Malaysia provided by petitioner based on third country average export price on the basis of Trademap data is unreliable and does not ensure fair comparison.. If such trademap data was reliable, petitioners have to explain why T/T data was used instead of DGCI&S published data. Dumping Margin for POI has to be determined based on responses to ensure adequacy and accuracy of data.
 - v. Exporters do not seek to dump product in any markets. There has been no case brought against TPPIC members on unfair trade, and a recent case brought by Vietnam was terminated without measures.

G.4. Examination by the Authority

37. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject country, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers/exporters have co-operated in this investigation by filing the prescribed questionnaire responses:
- i. Panel Plus MDF Company Limited, Thailand
 - ii. Robin Resources (Malaysia) SDN. BHD., Malaysia

Market Economy status for China PR

38. Article 15 of China PR's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) *The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*

(b) *In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.*

(c) *The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*

Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

39. The Authority notes that while the provisions of Article 15 (a) (ii) of China PR's Accession Protocol have expired with effect from 11 December 2016, the provision under Article 2.2.1.1 of the Anti-Dumping Agreement read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession protocol require criterion stipulated in Para 8 of the Annexure 1 of Anti-Dumping Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire for claiming MET status. The Authority notes that none of the producer/exporter from China PR have submitted any response. The Authority therefore considers it appropriate to proceed with para-7 of Annexure-I to the Rules for determination of normal value.

G.4.1 Normal Value determination for all producers/exporters from China PR

40. None of the producers from China PR have co-operated in the present investigation and provided any information for rebutting the non-market treatment as per Para 8(2) of Annexure 1 of the AD Rules. Therefore, the presumption of non-market economy as per Para 8(2) of Annexure 1 of the AD Rules remains un-rebutted. The Authority, therefore, has determined the Normal value in accordance with Para 7 of Annexure I to the AD Rules.
41. The Authority explored the option of construction of normal value as per the hierarchy laid down in Para 7 of Annexure-I to the Rules which provides that normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin.
42. The Authority has, constructed the normal value for China PR on the basis of cost of production in India, duly adjusted, including selling, general and administrative plus reasonable profits. The constructed normal value so determined for Chinese producers/exporters is mentioned in the dumping margin table below.

G.4.2 Normal Value determination for producers/exporters from Thailand

Panel Plus MDF Co. Ltd.

43. The Authority notes that Panel Plus MDF Co. Ltd. is a producer and exporter of the subject goods based in Thailand. Its related trader, namely, Panel Plus Co. Ltd. has also filed the questionnaire response. Panel Plus MDF Co. Ltd. has claimed normal value on the basis of sales made in the

domestic market. As per information available in the EQ response, during the period of investigation, the ordinary course of trade (80:20) test conducted on the domestic sales of Panel Plus MDF Co. shows ***% of sales as profitable. Therefore, normal value of the subject goods in the POI has been determined by taking only profitable domestic sales in the subject country. Panel Plus MDF Co. has claimed adjustments on account of inland freight and bank charges. Authority has allowed the same after due verification and normal value thus arrived is shown in dumping margin table below.

Normal value for all non-cooperative producers/exporters from Thailand.

44. Normal Value for non-cooperative producers/exporters from Thailand has been determined on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

G. 4.3 Normal Value determination for producers/exporters from Malaysia

Robin Resources (Malaysia) SDN. BHD.

45. The Authority notes that Robin Resources (Malaysia) SDN. BHD. is a producer and exporter of the subject goods based in Malaysia. Robin Resources (Malaysia) SDN. BHD. has claimed normal value on the basis of sales made in the domestic market. As per information available in the EQ response, during the period of investigation, the ordinary course of trade (80:20) test conducted on the domestic sales of Robin Resources (Malaysia) SDN. BHD. shows *** % sales as profitable. Therefore, normal value of the subject goods in the POI has been determined by taking average price of total domestic sales in the Malaysia. Robin Resources (Malaysia) SDN. BHD. has claimed adjustments on account of inland freight, credit cost and bank charges. Authority has allowed the same after due verification and normal value thus arrived is shown in dumping margin table below.

Normal value for all non-cooperative producers/exporters from Malaysia

46. Normal Value for non-cooperative producers/exporters from Malaysia has been determined on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

G.4.4 Normal Value determination for producers/exporters from Sri Lanka

47. The Authority notes that none of the producers/exporters from Sri Lanka have filed Exporter Questionnaire Response. In view of non-cooperation from all the producers/exporters in Sri Lanka, the Authority has determined normal value on the basis of best available information in terms of Rule 6(8) and the same is indicated in the dumping margin table given below.

G4.5 Export Price

Determination of export price in respect of producers/exporters from Thailand

Panel Plus MDF Co. Ltd. (Exporter/Producer)

48. Panel Plus MDF Co. Ltd. has filed questionnaire response along with its related trader, namely Panel Plus Co. Ltd. The Authority, however, notes that Panel Plus MDF Co. has exported the product under consideration directly to India during the period of investigation. Adjustments have been made on account of inland transportation, port and other related expenses, credit cost and bank charges as claimed by the exporter in its response to the questionnaire in order to arrive at the net export price at ex-factory level. Accordingly, the net export price at ex-factory level for Panel Plus MDF Co. Ltd. has been determined, which is indicated in the Dumping Margin Table below.

Other producers and exporters from Thailand

49. Since no response has been received from any other producer/exporter of the subject goods from the Thailand, the Authority has determined export price as per facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules in respect of other producers/exporters from Thailand.

Determination of export price in respect of producers/exporters from Malaysia

Robin Resources (Malaysia) SDN. BHD.

50. Robin Resources (Malaysia) SDN. BHD. has exported the product under consideration directly to India during the period of investigation. Adjustments have been made on account of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses and commissions, as claimed by the exporter in its response to the questionnaire in order to arrive at the net export price at ex-factory level. Accordingly, the net export price at ex-factory level for Robin Resources (Malaysia) SDN. BHD. has been determined, which is indicated in the Dumping Margin Table below.

Other producers and exporters from Malaysia

51. Since no response has been received from any other producer/exporter of the subject goods from the Malaysia, the Authority has determined export price as per facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules in respect of other producers/exporters from Malaysia.

Determination of export price in respect of Non-cooperative Exporters/ Producers from China PR and Sri Lanka

52. The Authority notes that none of the producers/exporters from Sri Lanka and China PR have filed Exporter Questionnaire Response. In view of non-cooperation, the Authority has determined export price on the basis of facts available in terms of Rule 6(8), in respect of exporters from China PR and Sri Lanka. The same is indicated in the dumping margin table given below.

G.4.6 Dumping Margin

53. Considering the normal value and export price as above, the dumping margins for all producers/exporters of the subject goods from the subject country is determined as below.

S.No.	Producer	Export Volume	Normal Value	Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin%	Range
		CBM	US\$/MT	US\$/MT	US\$/MT	%	%
1.	Panel Plus MDF Co. Ltd., Thailand	***	***	***	***	***	10-20
2.	Non-cooperative producer/exporter from Thailand	***	***	***	***	***	25-35
3.	Robin Resources (Malaysia) SDN. BHD., Malaysia	***	***	***	***	***	0-10
4.	Non-cooperative producer/exporter from Malaysia	***	***	***	***	***	15-25
5.	All producers/exporters from China PR	***	***	***	***	***	Negative
6.	All producers/exporters from Sri Lanka	***	***	***	***	***	30-40

H. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

54. Rule 11 of the Rules read with Annexure-II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....*”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
55. Rule 23 of the Rules provides that the provisions of Rule 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19 and 20 shall apply mutatis mutandis in case of a review. The Authority in its examination has evaluated the injury parameters which are required under Rule 11 and Annexure II of the Rules and has also examined as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
56. The Authority notes that the application for imposition of antidumping duty has been filed by M/s Greenply Industries Limited / Greenpanel Industries Limited, Century Plyboards (India) Ltd. and

Rushil Décor Limited. In terms of Rule 2(b) of the Rules, the Applicants have been treated as the domestic industry for the purpose of this investigation. Therefore, the cost and injury information of the Applicants, constituting the domestic industry, have been examined.

H.1 Submissions by the domestic industry

57. The submissions of the domestic industry with regard to injury and causal link are reproduced herein below:
- i. Cumulative assessment of the effects of likely dumped imports in the course of their likelihood-of-injury determinations is appropriate in the present investigation.
 - ii. Demand has increased throughout the injury period and the increase has been substantial.
 - iii. Imports from subject countries have increased throughout the injury period with a slight decline during period of investigation. However, the levels of imports in period of investigation is higher than as compared to base year as well as 2016-17 despite anti-dumping duty in existence.
 - iv. The subject countries hold a significant 28% share in the total imports of the subject goods in the country.
 - v. Imports from subject countries have increased despite existence of anti-dumping duty and the increase in capacities by Domestic Industry to overcome the demand-supply gap in the country.
 - vi. Imports from all subject countries are undercutting the prices of the domestic industry. The imports from Sri Lanka and Malaysia are undercutting the prices of the domestic industry.
 - vii. The Domestic Industry is facing price suppression and depression from the prices of the dumped imports from the subject countries. During period of investigation, when the cost of the domestic industry has increased as compared to 2017-18, domestic industry has been forced to reduce its selling price due to dumped imports.
 - viii. The profitability of the domestic industry has significantly declined in the period of investigation due to presence of dumped imports. The domestic industry is faced with decline in cash profits and return on investments. In the event of cessation of duties, the profitability of the domestic industry would be further impacted.
 - ix. The inventories with the domestic industry have significantly increased throughout the injury period despite offering suboptimal prices.
 - x. While the performance of the domestic industry was reasonable during the period 2016-18 and 2017-18, the domestic industry has once again suffered deterioration in performance due to dumping from subject countries.
 - xi. The imports from the subject countries have continued at dumped prices in the POI.
 - xii. The imports from the subject countries are undercutting and depressing the prices of the Domestic Industry.
 - xiii. The producers in the subject countries have surplus capacities. In the event of cessation of anti-dumping duty, these surplus capacities will be diverted to India.
 - xiv. In the event of cessation of the duty, the consequent increase in subject imports would force the Domestic Industry to reduce its prices significantly.
 - xv. In case prices are reduced, the profitability of the Domestic Industry would be impacted. Further decline in profits would lead to a major decline in cash flow and return on investment.
 - xvi. In case the Domestic Industry chooses to maintain its normal price levels, it is likely to lead to loss of sales volumes.
 - xvii. In case the loss of sales volumes is preferred by the Domestic Industry, it would lead to much bigger injury since inventories would rise while production, capacity utilization, and productivity would decline.
 - xviii. Imports from Malaysia has significantly increased.
 - xix. On the price levels being in the overall interest of India, it is submitted that the domestic industry is responsible and responsive. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to

eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of antidumping measures would not restrict imports from the subject country/territory in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

- xx. Public statements in the Annual Report do not alter the conclusion that dumping of the product has contributed to injury to the domestic industry. It has been wrongly assumed that dumping is the sole cause of injury. The statements in the annual report are not with regard to deterioration in performance of domestic industry over the injury period and they are concerned with overall operations of the company.

H.2 Submissions by other interested parties

58. The submissions of other interested parties with regard to injury and causal link are reproduced herein below:

- i. As noted from the public Annual Report, Indian producers are experiencing impressive growth rates even with newly installed capacities.
- ii. Export volumes from Thailand are negligible both in terms of total imports and market share.
- iii. Export from Thailand have not caused or contributed to the alleged continuation of injury.
- iv. Thai exporters are not dumping anywhere globally and believe in selling at fair prices.
- v. GreenPly Industries Ltd./ GreenPanel Industries Ltd. have witnessed strong growth in revenues with healthy profit margins in 2018 and 2019.
- vi. Relative decline in profits in 2019, is attributable to increased finance costs and these are most likely linked to increase in capacity.
- vii. Performance for CenturyPly has also seen positive growth, as per public documents.
- viii. In public documents, no mention is made of any problem due to imports and dumping of the PUC.
- ix. Actual exports from Thailand for the PUC stands at about 500-800 MT, which are lesser than the import statistics used by the petitioners.
- x. During the POI, the share of total imports is less than 1% and in terms of market share of the Indian domestic market and consumption, it is far less than 1%. Selling prices are the highest amongst the subject countries and fourth highest amongst the 21 countries that supplied the subject goods during the investigations.
- xi. Based on the Indian import statistics, Thai CIF prices are the highest amongst the exporting countries under investigation.
- xii. There is no undercutting, as acknowledged by the Petitioners. There may be a price effect, but the volumes are insignificant.
- xiii. The NIP calculations of industry would mean that almost all countries are underselling.
- xiv. Cost of production should be re-examined owing to the finance costs due to increased investments.
- xv. Petitioners made profits despite high costs for increase in capacities.
- xvi. Reduction in profits is more likely attributable to the increase in costs associated to the new investments.
- xvii. Subject imports did not cause any continued injury to the domestic Industry. Domestic Industry is not vulnerable to imports from the exporters. Volume parameters have gone up and price parameters were in the positive region. Slight dip in profitability cannot be attributed to subject imports as higher imports are taking place from other countries.
- xviii. The domestic industry seemingly seeks to increase prices when their performance has been very impressive. The interested parties have relied upon a Statement by Chairman of Century Plyboards India, Sajjan Bhajanka, wherein he has stated that the key growth driver of the

performance during year under review was the MDF business and a 65% capacity utilization was achieved in FY19, 161.11% increase in revenue from H113.11 crore in FY18 to H295.35 crore in FY19.

- xix. The injury and causal link claimed by petitioners is not true. All the volume parameters of the petitioners such as capacity, production, sales etc. have gone up and even price parameters were in the positive region and any slight dip in the profitability cannot be attributed to subject imports as imports at much higher level were taking place from other countries. The subject imports did not cause any continued injury to the domestic industry and the injury as claimed cannot be linked to the subject imports.
- xx. The domestic industry has been performing in a stable manner over the years and did not show any continued injury in the POI or in the injury period. The overall situation justifies expiry of present anti-dumping duties applicable on imports of subject goods from Thailand.

H.3. Examination by the Authority

59. The Authority has taken note of the submissions made by the interested parties. Annexure-II of the Anti-Dumping Rules provides for objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in domestic market for the like articles; and (b) the consequent impact on domestic producers of such products.
60. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, 1975, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time-to-time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of the order of such extension.
61. In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject countries.
62. It is not necessary that all parameters of injury show deterioration. Some parameters may show deterioration, while some others may not. The Authority considers all injury parameters and, thereafter, concludes whether the domestic industry has suffered injury due to dumping or not. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and arguments submitted by the domestic industry and other interested parties.

H.3.1. ASSESSMENT OF DEMAND

63. The Authority has determined demand or apparent consumption of the product in India, as the sum of domestic sales of the Indian producers, and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Demand in India	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI	
					Annualized	Actual
Sales of Domestic Industry	CBM	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>		<i>100</i>	<i>95</i>	<i>106</i>	<i>134</i>	<i>134</i>
Sales of Other Indian Producers	CBM	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>		<i>100</i>	<i>104</i>	<i>104</i>	<i>119</i>	<i>119</i>
Imports from- Subject Countries	CBM	34,287	33,391	44,423	39,446	59,170
China	CBM	179	400	466	74	112
Malaysia	CBM	12,501	18,848	27,904	30,716	46,074
Thailand	CBM	3,406	2,271	3,681	1,914	2,872
Sri Lanka	CBM	18,201	11,872	12,371	6,741	10,112

Other Countries attracting ADD	CBM	61,099	92,335	1,41,284	97,447	1,46,171	
Indonesia	CBM	16,977	6,724	856	97	145	
Vietnam	CBM	44,123	85,611	1,40,427	97,350	1,46,026	
Imports from other countries	CBM	17,881	23,094	22,302	18,306	27,459	
Total Demand in India	CBM	***	***	***	***	***	
<i>Trend</i>		100	108	123	128	128	
Market Share in Demand							
Domestic industry	%	***	***	***	***	***	
<i>Trend</i>		100	88	86	105	105	
Other Indian Producers	%	***	***	***	***	***	
<i>Trend</i>		100	97	85	93	93	
Imports from- Subject Countries	%	7	6	7	6	6	
China	%	0	0	0	0	0	
Malaysia	%	3	4	5	5	5	
Thailand	%	1	0	1	0	0	
Sri lanka	%	4	2	2	1	1	
Other Countries attracting ADD	%	12	17	23	15	15	
Indonesia	%	3	1	0	0	0	
Vietnam	%	9	16	23	15	15	
Other Countries	%	4	4	4	3	3	
Total Demand	%	100	100	100	100	100	

64. The Authority notes that the demand in India has increased throughout the injury period and in the POI.

H.3.2. VOLUME EFFECT OF DUMPED IMPORTS

65. The effects of the volume of dumped imports from the subject countries as well as imports from other countries have been examined by the Authority as follows:-

Import Volume	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI	
					Annualized	Actual
Imports from Subject Countries	CBM	34,287	33,391	44,423	39,446	59,170
China	CBM	179	400	466	74	112
Malaysia	CBM	12,501	18,848	27,904	30,716	46,074
Thailand	CBM	3,406	2,271	3,681	1,914	2,872
Sri Lanka	CBM	18,201	11,872	12,371	6,741	10,112
Other Countries attracting ADD	CBM	61,099	92,335	1,41,284	97,447	1,46,171
Indonesia	CBM	16,977	6,724	856	97	145
Vietnam	CBM	44,123	85,611	1,40,427	97,350	1,46,026
Imports from other countries	CBM	17,881	23,094	22,302	18,306	27,459
Total Import Volume	CBM	1,13,267	1,48,820	2,08,008	1,55,199	2,32,799

Subject Countries Imports in relation to						
Imports	%	30.27	22.44	21.36	25.42	25.42
Production	%	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	94	120	81	81
Consumption	%	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	122	149	107	107

66. The Authority notes that the volume of dumped imports of the product under consideration from the subject countries has increased in 2017-18 and declined in POI. However, compared to base year 2015-16, the imports from subject countries have increased in the POI.

H.3.3. PRICE EFFECT OF THE DUMPED IMPORTS

67. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, the Authority is required to consider the effect of the dumped imports on domestic prices in terms of price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any.

i. Price undercutting

68. With regard to the effect of dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product from the subject countries and the average selling price of the domestic industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at ex-factory level.

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Net sales realization	Rs/CBM	***	***	***	***
Subject countries as a whole					
Landed price of imports without ADD	Rs/CBM	18,215	15,734	15,582	15,063
Price undercutting	Rs/CBM	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range	10-20	20-30	20-30	20-30
China					
Landed price of imports without ADD	Rs/CBM	26,495	21,588	19,495	22,214
Price undercutting	Rs/CBM	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range	Negative	Negative	10-20	Negative
Malaysia					
Landed price of imports without ADD	Rs/CBM	16,621	14,589	14,979	14,899
Price undercutting	Rs/CBM	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range	20-30	30-40	30-40	20-30
Thailand					
Landed price of imports without ADD	Rs/CBM	16,980	17,304	17,333	15,354
Price undercutting	Rs/CBM	***	***	***	***

Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range	20-30	10-20	20-30	20-30
Sri Lanka					
Landed price of imports without ADD	Rs/CBM	19,461	17,054	16,274	15,651
Price undercutting	Rs/CBM	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range	10-20	20-30	20-30	20-30

69. It is noted the import prices from Malaysia, Thailand and Sri Lanka are undercutting the prices of the domestic industry. The price undercutting with respect to China is negative.

ii. **Price Suppression/ Depression**

70. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority notes the changes in the costs and prices over the injury period. The position is shown as per the table below:

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Cost of Sales	Rs/CBM	***	***	***	***
<i>Trend</i>		<i>100</i>	<i>94</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Selling Price	Rs/CBM	***	***	***	***
<i>Trend</i>		<i>100</i>	<i>99</i>	<i>102</i>	<i>90</i>
Landed Price from subject countries	Rs/CBM	18,215	15,734	15,582	15,063
<i>Trend</i>		<i>100</i>	<i>86</i>	<i>86</i>	<i>83</i>

71. It is noted that the landed price of imports from subject countries is below the cost of sales during the period of investigation. Consequently, when the cost has declined over the injury period, selling price of the domestic industry has declined more than cost decline. The imports are suppressing the prices of the domestic industry.

iii. **Price underselling**

72. The price underselling has been evaluated by comparing the non-injurious price with the landed price of the subject imports.

Particulars	UOM	China PR	Malaysia	Thailand	Sri Lanka
Import Volume	CBM	***	***	***	***
Non-Injurious Price (NIP)	Rs/CBM	***	***	***	***
Landed Price	Rs/CBM	22,213.7	14,898.8	15,354.1	15,651.4
Injury Margin	Rs/CBM	***	***	***	***
Injury Margin	%	***	***	***	***
Injury Margin	%, Range	Negative	10-20	10-20	10-20

73. It is seen that the price underselling is positive for each of the subject countries except for China PR.

H.3.4. Impact on Economic Parameters of the Domestic Industry

74. Annexure – II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. The Anti-Dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

a. Capacity, Production, Capacity Utilization and Sales

75. The Authority has considered capacity, production, capacity utilization and sales volume of the domestic industry over the injury period and notes as follows:

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI	
					Annualized	Actual
Installed Capacity-Plant	CBM	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	100	137	284	284
Production Quantity-Plant	CBM	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	108	128	185	185
Capacity Utilization-Plant	%	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	108	94	65	65
Production Quantity-PUC	CBM	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	103	113	171	171
Domestic Sales-PUC	CBM	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	95	106	134	134

76. It is noted from the above table that –

- The capacity of the domestic industry has increased in 2017-18 and in the POI. The Authority considers that the increase in capacity is due to the entry of Century Plyboards and the establishment of new capacities by Greenply/Greenpanel and Century Plyboards.
- The production quantity of the domestic industry increased in 2017-18 and in the POI.
- The capacity utilization has declined in 2017-18 and thereafter in the POI.
- The domestic sales has shown the same trend as production.

b. Market Share of Domestic Industry in Demand

77. Market share of the domestic industry have been examined as below: –

Particular	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
					Actual
Domestic industry	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	88	86	105
Other Indian Producers	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	97	85	93
Imports from- Subject	%	7	6	7	6

Countries					
Other Countries attracting ADD (Vietnam & Indonesia)	%	12	17	23	15
Other Countries	%	4	4	4	3
Total Demand	%	100	100	100	100

78. It is noted that the market share of the subject countries have remained more or less same while the market share of the domestic industry has increased in the POI. The domestic industry has submitted that the increase in market share is due to capacity additions and offering suboptimal prices to sustain in the market.

c. Inventories

79. The data relating to inventory of the subject goods are shown in the following table:

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Inventory – Average	CBM	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	151	318	431

80. The Authority notes that the inventories with the domestic industry has increased substantially over the injury period and further in the POI.

d. Profit or loss, cash profits and return on investment

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI	
					Annualized	Actual
Cost of Sales	Rs/CBM	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	94	100	100	100
Selling price	Rs/CBM	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	99	102	90	90
Profit before tax	Rs/CBM	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	116	113	51	51
Total Profit before Tax	Rs.Lacs	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	111	120	68	68
Total Profit before interest	Rs.Lacs	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	105	114	77	77
Cash Profit	Rs.Lacs	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	107	133	96	96
Return on capital employed	%	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	122	76	29	29

81. Performance of the domestic industry has been examined

82. It is noted that the profitability, cash profits and return on capital employed of the domestic industry increased consistently till 2016-17 but thereafter declined in the POI.

e. Employment, wages and productivity

83. The situation of the domestic industry with regard to employment, wages and productivity was as below –

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI	
					Annualized	Actual
Employment	Nos	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	102	155	237	237
Productivity per day	CBM	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	103	113	171	171
Productivity per Employee	CBM	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	101	73	72	72
Wages	Rs.Lacs	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	101	134	247	247

84. It is noted that the employment, wages and productivity per day have shown a substantial increase in 2017-18 and in the POI. The domestic industry has submitted that these parameters are not reflective of the impact of dumped imports on the domestic industry.

f. Growth

85. Examination of growth parameters of the domestic industry during the injury period is shown below –

Particular	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI Annualized
Production (PUC)	%	-	2.79	9.92	51.51
Domestic Sales Volume	%	-	(4.78)	11.81	25.96
Capacity utilization	%	-	8.02	(13.03)	(30.71)
Profit/Loss domestic(Per CBM)	%	-	16.09	(2.76)	(54.90)
ROI	%	-	22.03	(37.80)	(61.18)
Cash Profit	%	-	7	20	(26)

86. It is noted that the growth of the domestic industry in terms of production and sales is positive, whereas the growth in terms of capacity utilization, profits, and return on capital employed is negative.

g. Factors affecting domestic prices

87. The Authority notes that the domestic prices have been affected due to the presence of dumped imports in the country.

h. Ability to raise fresh investment

88. The domestic industry has claimed that the Domestic Industry has been operating at low capacity utilization despite significant demand in the country and it has weakened the ability of the Domestic Industry to raise capital investment.

Conclusion on injury

89. Considering various parameters relating to material injury, the Authority notes that there has been increase in the volume of dumped imports of the subject goods, in absolute terms. Imports are undercutting the domestic prices in the POI, and the domestic industry was suffering a suppressing effect on the domestic selling prices. Overall performance of the domestic industry have deteriorated in respect of various economic parameters such as capacity utilization, profits, cash profits and ROI in the POI. Inventories with the domestic industry has increased.

I. CAUSAL LINK

90. As per the AD Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than dumped imports which are injuring or are likely to cause injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. While the present investigation is a sunset review investigation and causal link has already been examined in original

investigation, the Authority examined whether other known listed factors have caused or are likely to cause injury to the domestic industry. It was examined whether other factors listed under the AD Rules could have contributed or are likely to contribute to the injury suffered by the domestic industry.

a. Volume and price of imports from third country:

91. The Authority notes that the volume of imports of the product under consideration from other countries are either attracting Anti-dumping duty or are at higher prices.

b. Contraction in Demand and/or Change in Pattern of consumption

92. The demand of the subject goods has increased throughout the injury period. The pattern of consumption with regard to product under consideration has not undergone any change. Changes in the pattern of consumption could not have, therefore, contributed to the injury to the domestic industry.

c. Export Performance

93. Applicants have exported the subject goods. However, they have claimed likelihood of injury in the domestic operations. Applicants have provided costing and injury information for domestic sales separately. Hence, likelihood of injury considered cannot be attributed to exports.

d. Development of Technology

94. None of the interested parties have raised any issue with regard to developments in technology as being the cause of injury to the domestic industry.

e. Performance of other products of the company

95. The Authority notes that no submission has been made by any of the interested parties to the effect that the performance of other products being produced and sold by the applicants is a possible cause of injury to the domestic industry.

f. Trade Restrictive Practices and Competition between Foreign and Domestic producers

96. The import of the subject goods is not restricted in any manner and the same are freely importable in the country. The domestic producers compete with the landed prices of the subject goods. The price of the domestic industry is influenced substantially by the landed prices of subject goods. Moreover, no evidence has been submitted by any interested party to suggest that the conditions of competition between foreign and domestic producers have undergone any change.

g. Productivity of the domestic industry

97. The Authority notes that no submissions have been made by either the domestic industry or any of the interested parties regarding possible injury to the domestic industry on account of productivity of the domestic industry.

J. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF INJURY

98. In a review investigation, the Authority has to determine whether the subject goods are continuing to enter or likely to enter the Indian market at dumped prices and whether injury to the domestic industry is likely to continue or recur due to these dumped imports if the duty is removed.

J.1. Submissions by the domestic industry

99. The domestic industry submitted as follows with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury –
- i. Producers in the subject countries maintain huge capacities.
 - ii. Due to excess capacities, the producers have also accumulated high inventories. The presence of these inventories in itself shows huge likelihood of increased exports to India on the event of cessation of anti-dumping duties.
 - iii. The producers/exporters from the subject countries have high export orientation. A large portion of their revenue is generated from export sales.
 - iv. The producers/exporters from the subject countries have significant unutilised capacities which can easily cater the entire demand in India.
 - v. The producers/exporters from the subject countries have freely disposable production capacities.

- vi. Producers in Thailand have either initiated capacity expansions or have proposed expansions in the recent periods. Expansions taking place despite ample capacities in Thailand.
- vii. The exporters from subject countries are prima-facie exporting the product under consideration to third countries at dumped prices.
- viii. There has been a decline in demand for the subject goods in China.
- ix. The questionnaire responses filed by exporters/producers also clearly establish that there is a likelihood of dumping and consequent injury to the domestic industry. The responses filed by the exporters show: (1) surplus and unutilized capacities with the exporters; (2) freely disposable capacities with the exporters; (3) increase in inventories; (4) significant decline in selling price of exports to India; (5) export orientation.
- x. The exporters have acknowledged their intention to export to India in their responses. They have also acknowledged that the impact of the existing ADD has forced them to export to other countries. Therefore, it is very likely that these imports will be redirected to India in the event of cessation of anti-dumping duty.
- xi. The demand of the domestic industry has declined in China PR over the period. With presence of excess capacities in China, the decline in demand in china will force the producers to look for the more lucrative markets.
- xii. There exists likelihood of continuation or recurrence of dumping and likelihood of continuation or recurrence of injury.
- xiii. The exporters have not provided any evidence to dispute the claims of the domestic industry on likelihood.
- xiv. As per the Part 2 of the questionnaire response, Panel Plus MDF Co. Ltd. has increased its capacities in the year Jan-Dec 18 by 76%. The capacity utilization of the company has declined by 45%. The inventories have increased by 53% in 2018 and 19% during period of investigation. With decline in capacity utilization by 45% shows that the exporter has significant unutilized capacities.
- xv. There is a significant increase in inventories. Increase in inventories in one of the parameters of threat analysis as well. There need not be any further analysis required for establishing likelihood. Increase in inventories of the exporter is sufficient.
- xvi. The Part 2 of the questionnaire shows that the capacity utilization of Robin Resources (Malaysia)SDN. BHD. has declined by 39% in the period of investigation, which establishes increase in unutilized capacities. If the domestic sales of the exporter have increased and still capacity utilization declined, it means that the unutilized capacities are meant for exports. However, the submissions of the exporter is contradictory to the information provided in Part 2 of the response. The submissions states that Domestic uptake was robust however response shows that domestic sales have declined by 9%.
- xvii. Now that the responding exporters have filed the responses including third country export price, the likelihood analysis can be based on the exporter's data subject to adequacy and accuracy of the information. Further, the Authority may determine likelihood both from the questionnaire response as well as from exporting countries' trade data.
- xviii. As regards distortions in capacity and production figures for Thailand, the domestic industry has provided information to the best of its abilities. Further the capacities of PUC and NPUC can be used interchangeably. Now that the exporter has provided actual information regarding their production and capacities, same may be relied upon subject to adequacy and accuracy of the information.

J.2. Submissions by other interested parties

- 100. Following submissions have been made by other interested parties with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury:
 - i. There is no likelihood as main focus of the producers is on domestic market, Middle East and the ASEAN market.

- ii. Capacities and utilization rates and production numbers of Thailand producers provided in the petition are inaccurate and is not clear if claim is made for PUC alone or for MDF. There is no surplus capacity that would enter India in the absence of measures. The concern of Thai exporters is to maintain the existing customer base in India, and not to be closed out from the benefits of a presence on a highly innovative market.
- iii. Out of the total capacity, a number of producers do not even produce the PUC. Capacities cannot be switched according to market demands etc.
- iv. There is no likelihood as can be established from the fact that no other country has imposed ADD on Thai exports.
- v. Based on information from Thai producers, their average export prices are about 10% above the domestic selling prices for the same specifications being exported and the same level of trade.
- vi. A large portion of the capacities is already dedicated to non-PUC and other markets like Middle East and ASEAN. The Indian market is not considered core market for Thailand, either past present or future.
- vii. In case of HS 441113, Over 59% of total imports of PUC from Thailand are destined for the Middle East and 15 % to the ASEAN. Over the period 2015 to 2019, imports to the Middle East have increased by 82,025 MT. A significant volume of these exports is for thickness of less than 5mm. Over 95% of the 12,000 MT exported to India in 2019 is not PUC.
- viii. Exports of HS 441114 to India are less than 0.3% and the exports are mostly destined for Middle East and ASEAN.
- ix. Information provided on likelihood of dumping and injury is grossly insufficient and unreliable to prove the conditions for continuation of existing anti-dumping duty in an expiry review as mandated in the Rules. The parties have relied on Rule 23 of the Anti-dumping Rules in this regard. The claimant domestic industry has to demonstrate the consequences of such an expiry based on facts and not merely on presumptions, assumptions and conjectures. Exporters have provided details to show absence of likelihood and same has to be considered.
- x. Parameters relevant to gauge the possibilities of likelihood of dumping and injury clearly shows no likelihood of dumping and injury in the event of expiry of duties on Thailand. The exporters are operating in a well-established market and the expiry of the duties will not change the behaviour of the exporters in any manner. There is no compulsion to export to India by reducing the prices in the event of expiry of duties.
- xi. The details of capacity, third country exports details etc. provided in the petition are misleading and cannot be relied upon. The Authority must use the data provided in the Responses for all determination of current and likelihood parameters.
- xii. Exports from Malaysian exporter will not go up as alleged by the petitioner in the event of expiry of duty and trend of exports after no levy of ADD in the original case. Certain users in India find its product the most suitable and the exporter does not have to resort to any price distortion practices to cater to such users.
- xiii. Claims of excess unutilized capacities are not true since the capacities remained same in POI and Post POI while capacity utilization increased and the exporter has been operating in the range of 90 – 99%. Production slightly increased with declines in exports to India and third countries. Domestic uptake was robust. Data shows that the capacity utilization of the exporter is not directly linked to its export market and domestic supplies hold the key.
- xiv. . Claims of excess unutilized capacities are not true since the exporter's capacity remained same in POI and post POI and utilization has been between a reasonable level of 75% - 85%. The real utilization at the plant level is even higher on account of the product mix.
- xv. Likelihood examination is a forward looking statement and the domestic industry has referred to the movements in parameters during the injury period. The Capacity of the Company remained same in the post POI period also. There are no threats from Panel Plus as the company is not sitting on any significant excess capacity etc.

- xvi. Participation by the party is to refute the wrong claims of the DI and it doesn't show Indian market is lucrative for exporters.
- xvii. The absence of injury from continued imports indicates absence of likelihood of injury also in the event of expiry of present duties.
- xviii. There are no threats from Robin Resources as the company is not sitting on any significant excess capacity etc. and the dumping margin determined for the company in the past was also either negative or very negligible only.
- xix. There is a lack of excess capacity that would undermine the possibility of Thai industry to increase the exports to India, in conjunction with the higher average selling price of Thai producers to major export markets comparing to domestic market.

J.3. Examination by the Authority

101. The Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of injury considering the requirement laid down under Section 9A(5), Rule 23 and parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure – II (vii) of the Anti-Dumping Rules, and other relevant factors brought on record by the interested parties. The Authority notes as under.
102. The present investigation is a sunset review of duties imposed on the imports of subject goods from the subject countries. Under the Rules, it is required to be determined whether continued imposition of antidumping duty is warranted. This also requires an examination of whether the duty imposed is serving the intended purpose.
103. Further, the Authority has also examined other relevant factors which could have a bearing on the likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry. The examination of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry is as follows:

i. **Significant production capacities with the producers/exporters in subject countries and ability of other export markets to absorb additional capacities**

104. Analysis of the questionnaire responses filed by the responding exporters shows as follows:

Particular	Unit	Robin Resources (Malaysia) Sdn. Bhd. Malaysia	Panel Plus MDF Co. Thailand
Capacity	CBM	***	***
Plant Production	CBM	***	***
Capacity Utilization	%	***	***
Production-PUC	CBM	***	***
Domestic Sales	CBM	***	***
Exports to India	CBM	***	***
Exports to Other Countries	CBM	***	***

105. Further information provided by the domestic industry with regard to subject countries shows as follows with regard to capacities.

Producer	Capacities (MT)
DARE	11,25,000
Guangdong Weihua	10,12,500
Vanachai Group Public Company Limited, Thailand	8,77,500
Panel Plus Thailand	5,02,500
Green Panel Products	3,75,000
Metro MDF Co. Ltd.	3,75,000
Advance Fiber Co. Ltd.	3,37,500

Guangzhou Huafangzhou Wood Co., Ltd.	2,62,500
M/S Dongwha Global Sales Sdn. Bhd., Malaysia	2,70,000
MDF Co. Ltd.	1,92,750
S. Kijchai Enterprises Co. Ltd.	2,10,000
DAIKEN Group	1,72,500
Wisewoods	1,80,000
M/S MerbokMDF Lanka (Private) Limited, Sri Lanka	1,35,000
M/S Robin Resources (Malaysia) Sdn Bhd., Malaysia	1,46,250
S.P.B.P. Panel Industries Co. Ltd.	1,50,000
M/S Dongwha MDF (M) Sdn. Bhd., Malaysia	97,500
Yonglin Group	90,000
Magna Foremost	75,000
Yunfu Zhenying Wood Co. Ltd.	78,750
Sagamat Panel Board SDH BHD	60,000

106. It is noted that the capacities indicated in the report furnished by the domestic industry in its application suggest capacities with these foreign producers far in excess of demand in India.

i. Increase in Inventories

107. The Authority notes that the responses from the exporters show that the inventories with the responding exporters have increased. The Authority also notes that the producers in the subject countries are export oriented. In the event of cessation of the anti-dumping duty, it is likely that the subject countries will increase their exports to India.

ii. Third country dumping and injury

108. The following exporters have filed questionnaire responses in the form and manner prescribed, including questionnaire response relevant for sunset review investigation. Therefore, the Authority has examined the questionnaire response and ascertained the volume of exports by these exporters to third countries at prices below normal value (i.e., dumped) and injurious (i.e., below NIP of the domestic industry).

- i. Panel Plus MDF Co. Ltd.
- ii. Robin Resources (Malaysia) SDN. BHD

109. The table below shows volume of exports by these exporters to third countries at dumped, attractive and injurious prices.

POI Period Robin Resources (Malaysia) SDN. BHD - Malaysia

	Exports to India CBM	Exports to Third country CBM	Total CBM
Volumes below NIP	***	***	***
Volume above NIP	***	***	***
Volumes below normal value	***	***	***
Volume above normal value	***	***	***
Demand in India	***	***	***
% in relation to demand	***	***	***
Volume below normal value (i.e., dumped) in %	***	***	***
Volume below NIP (i.e., injurious) in %	***	***	***

POI Period – Panel Plus MDF Co. Ltd Thailand

	Exports to India CBM	Exports to Third country CBM	Total CBM
Volumes below NIP	***	***	***
Volume above NIP	***	***	***
Volumes below normal value	***	***	***
Volume above normal value	***	***	***
Demand in India	***	***	***
% in relation to demand	***	***	***
Volume below normal value (i.e., dumped) in %	***	***	***
Volume below NIP (i.e., injurious) in %	***	***	***

110. It is seen that the volume of exports by Robin Resources and Panel Plus to rest of world at a price below normal value and NIP is quite significant. It is noted that whereas volume of exports to India by Robin Resources constituted ***% of its global exports; ***% of its production; and ***% of its capacity, the exports to India by Panel Plus constituted only ***% of its global exports, ***% of their production and ***% of its capacity. It is also noted that volume of exports to India by Robin Resources constituted ***% of imports from Malaysia.
111. It is seen that volume of exports to India by Panel Plus constituted ***% of imports from Thailand and ***% of imports from various sources. Imports from Malaysia and Thailand during POI constituted ***% and ***% of total imports into India during the POI. Further, the volume of exports of Panel Plus to India is quite insignificant.

K. MAGNITUDE OF INJURY AND INJURY MARGIN

112. The Authority has determined Non-Injurious Price for the domestic industry on the basis of principles laid down in anti-dumping Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The NIP of the domestic industry has been worked out and it has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining NIP, the best utilization of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been done with the utilities. The best utilization of production capacity over the injury period has been considered. The optimum production in POI has been calculated considering the best capacity utilization and the same production has been considered for arriving per unit fixed cost. No extraordinary or non-recurring expenses have been charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. Average Net Fixed Assets plus Average Working Capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure-III and being followed. The non-injurious price so determined has been compared with the landed price of imports from the subject country to determine the injury margin.
113. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry when compared with the landed value of the exports from the subject countries shows following injury margin during POI.

SN	Producer	NIP	Landed value	Injury margin	Injury margin	Injury margin
		Rs/CBM	Rs/CBM	Rs/CBM	%	Range
1.	Panel Plus MDF Co. Ltd., Thailand	***	***	***	***	Negative
2.	Non-cooperative producer/exporter from Thailand	***	***	***	***	0-10

3	Robin Resources (Malaysia) SDN. BHD., Malaysia	***	***	***	***	10-20
4	Non-cooperative producer/exporter from Malaysia	***	***	***	***	40-50
5	All producers/exporters from China PR	***	***	***	***	(15-25)
6	All producers/exporters from Sri Lanka	***	***	***	***	10-20

Conclusion on Likelihood of Dumping and Injury

114. The evidence on record show that there has been increase in the volume of dumped imports of the subject goods, in absolute terms. Imports are undercutting the domestic prices in the POI, and the domestic industry is suffering suppressing effect on the domestic selling prices. Overall performance of the domestic industry has deteriorated in respect of various economic parameters such as capacity utilization, profits, cash profits and ROI in the POI. Inventories with the domestic industry has increased. The information on record shows that the capacities with the producers in the subject countries is far higher than the domestic demand in India, and the subject countries are holding significant surplus capacities. The questionnaire responses of the exporters show high volume of exports to third countries at dumped and injurious prices. Thus, all these parameters indicate that in the event of cessation of ADD, the exporters in the subject countries are likely to intensify export of the product in India at dumped prices, leading to injury to the Domestic Industry.

L. POST DISCLOSURE COMMENTS

115. The Authority notes that most of the submissions made by the interested parties in response to the disclosure statement are repetitive in nature and the interested parties have largely reiterated their earlier submissions, which have already been examined and addressed by the Authority. Following are new submissions made by the domestic industry and other interested parties on the disclosure statement.

L.1 Submissions made by the domestic industry

116. The submissions made by the domestic industry on the disclosure statement are as follows:
- Methodology adopted by Authority in previous investigations will hold field unless interested parties establish a need for deviation. The facts regarding adoption of PCN are not new facts. The Authority had not adopted PCN in previous investigations.
 - The Authority is right in rejecting the responses filed by Advance Fibre Co. Ltd., Thailand and Wisewoods Co. Ltd., Thailand as the responses filed by them were grossly deficient.
 - Increase in imports is despite the existence of anti-dumping duty.
 - The increase in inventories is despite offering subject goods at sub-optimal prices.
 - In the event of cessation of anti-dumping duties, the profitability of the petitioning domestic industry would be further impacted.
 - Negative weighted average injury margin of Panel Plus is not sufficient to conclude absence of likelihood for Panel Plus. Significant exports made by Panel Plus are at prices below NIP.
 - Negative injury margin based on weighted average is insufficient to conclude absence of likelihood. Available information does not show export price to third countries as materially higher than export price to India. Reference is made to Kothari Sugars & Chemicals v. Designated Authority where transaction below NIP was allowed to be considered to calculate injury margin, which was also referred to in Honest Enterprises Ltd. v. Designated Authority.
 - Extension of duty has been recommended in past cases even after negative injury margin in the POI and therefore, there is no justification for withdrawal of duty on exporter merely due to negative injury margin.

- ix. The average injury margin in the present investigation is misleading and duty is required to be extended on Panel Plus, as injurious imports by Panel Plus is likely to cause injury to the domestic industry.
- x. The non-injurious price considered by the Authority is at a different level as compared to Net Sales Realization. Adjustments has to be made to either Net Sales Realization or non-injurious price in order to bring both at the same level.
- xi. There is continued dumping and injury to the domestic industry due to the presence of dumped imports from the subject countries. There also exists sufficient likelihood of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of anti-dumping duty.
- xii. Extension of anti-dumping duties will not be against public interest as domestic industry has increased capacities and is capable of catering to total demand in the country. India has become self-reliant.
- xiii. The objective of dumping law is to establish a level playing field and allow fair competition for the Indian industry. It will not restrict imports or affect availability of product to consumers.
- xiv. The interested parties are producers from Thailand and Malaysia who are naturally concerned only with their own interests and not India's interests. None of the consumers have raised concerns against extension of duty.

L.2 Submissions made by other interested parties

117. The submissions of other interested parties on disclosure statement are as under:

- i. Wisewoods Co. has fully co-operated with the present investigation and provided all documents and data accurately.
- ii. Wisewoods' business activities do not cause any injury to India and hence individual duties need to be accorded rather than mixing the duty rate with companies who have not cooperated in the investigation.
- iii. With regard to the view taken by the Authority on PCN methodology for dumping and injury margin determination in para 17, it is submitted that adoption of a past practice without looking at the merit of the claim in the present case is not justified. The normal value and export price be considered taking into account the comparable product type and such comparison is a basic requirement under the AD Agreement and also under the Indian AD Rules. The Company here has provided separate cost and price details of such types showing significant differences which alone justify a PCN to PCN comparison to determine dumping and injury margin.
- iv. Meagre 47% is not a sufficient percentage to determine standing as the injury claimed by petitioners holding such meagre share cannot be treated as representative of injury having been suffered by the Indian producers.
- v. The dumping margin as determined in the disclosure is the result of an inappropriate comparison of normal value and export price and fair determination of such margin by comparing the identical types would give a nil or very negligible dumping margin.
- vi. The petitioners did not face any adverse effects on account of some imports from subject countries. The Authority should note the larger fact that duties have been in force for quite some time on the subject goods from subject countries and the imports from subject countries were only about 6% of the Indian demand during the POI which is not any alarming level of imports. Nor such import can be perceived as having any threat of injury to the petitioners in the event of expiry of present duties.
- vii. The performance of the domestic industry has increased manifold in terms of volume parameters. There is no volume injury. The domestic industry has claimed some decline in the profitability in the POI. It may be noted in this regard that the imports from subject countries were not impacting the performance of the domestic industry in any manner and there were higher volumes of import taking place from other countries. The dip in profitability has been the result of down-time in the user industries, which had nothing to do with imports. The injury examination may be conducted in view of such broader economic realities and not on a narrow prism so as to conclude that there is injury. If the claims of price

- undercutting/underselling/suppression were true, then the domestic industry would not have increased the sales. Pricing was apparently impacted due to indigenous factors and not because of any alleged unfair competition from imports from subject countries.
- viii. The observation of likelihood of more exports in the event of expiry of duties as made in the disclosure is denied. Since the Authority has not disclosed any information under consideration even in indexed form other than the table at para 104, the party is not in any position to offer any meaningful comments and reiterates its submissions earlier made on likelihood.
 - ix. The observation that capacities with the producers in the subject countries are far higher than the domestic demand in India does not indicate any likelihood of dumping and injury in the event of expiry of duties. Merely showing capacity in subject countries higher than that of demand in India is not any parameter of likelihood examination. It should be demonstrated that all such capacities are excess and idle capacities and are waiting for the expiry of duty in India to be activated for India. Had the likelihood been so vigorous, then the imports in POI also would have been much higher and injurious and at a higher dumped rate.
 - x. The data on injury and limited information provided on likelihood shows that expiry of the existing anti-dumping duty is not likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
 - xi. The duties have met all its intended purposes in the present case and the present case is a fit case for recommending discontinuation of existing duties and we pray for the same.
 - xii. Thai exporters have not caused any injury to the domestic industry.
 - xiii. The rate of duty should be considered specifically for Advance Fibre Co. Ltd. as they have cooperated in this investigation.

L.3 Examination of the Authority

118. The Authority notes that most of the submissions by the domestic industry and other interested parties are repetitive in nature. These submissions have already been examined at appropriate places in this finding. Further, the Authority has examined additional/new relevant submissions of the interested parties as under:
- a. As regards absence of injury to the domestic industry, the same has been adequately examined. The Authority notes that the present investigation is a sunset review investigation and the Authority is required to consider both current and likely injury.
 - b. As regards PCN wise analysis, it is reiterated that that same issue was earlier dealt by the Authority in case of ADD investigation for the same product wherein it was decided not to adopt PCN methodology on this basis. No justification has been given by interested parties which justify the need for deviation from the previous findings.
 - c. As regards possibility of absence of dumping in case of PCN wise analysis, the Authority notes that the present investigation is a sunset review investigation and therefore even if there was no current dumping, the exporters are required to establish absence of likelihood of dumping and injury in the event of cessation of ADD.
 - d. As regards communication of deficiency to the interested parties from the Authority, it is noted that opportunity for rectification of deficiency cannot be utilised by interested parties to complete the questionnaire response and provide some new/ fresh information which was not provided at the stage of filing questionnaire response.
 - e. As regards likelihood examination, it is noted that likelihood determination is not limited to capacities with the responding exporters. All the factors listed in the relevant paragraphs hereinabove cumulatively show that in the event of cessation of ADD, the exporters in the subject countries are likely to intensify export of the product to India at dumped prices, leading to injury to the Domestic Industry.
 - f. As regards argument on the disclosure of likelihood information, it is noted that the information is based on responses filed by the exporters themselves. Since the information is only for one year, the same cannot be provided in indexed form.
 - g. As regards argument of weighted average negative injury margin of Panel Plus, it is noted the company is dumping the product into India despite anti-dumping duty in existence. Further the information provided by the company with regard to unutilized capacities, exports to third

countries, dumped and injurious exports to third countries clearly shows likelihood of dumping and injury in the event of cessation of ADD. The volume of current exports by Panel Plus to India is quite insignificant having regard to consumption in India, its exports to various countries globally, its production and installed capacities. These parameters collectively establish that the current injury margin is not representative of the likely behaviour of the exporter in the event of cessation of Anti-dumping duty.

- h. The Authority also considered the volume of exports to India by different cooperating exporters/producers. It is noted the quantum of ADD on Robin Resources was US\$ 5.72 per CBM. Its volume of exports to India increased significantly in relation to its exports to various countries and also in relation to total imports of PUC into India from Malaysia. Further, the quantum of ADD on Panel Plus was much higher (US\$ 45.27 per CBM) and accordingly its volume of exports to India is quite insignificant in relation to its exports to various countries and also in relation to imports of PUC into India from Thailand. Further, the volume of exports of both Robin Resources and Panel Plus to third countries at prices below normal value and NIP is quite significant, having regard to consumption in India. This indicates that in the event of cessation of ADD, the exporters in the subject countries are likely to intensify export of the product in India at dumped prices, leading to injury to the Domestic Industry.

M. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST

119. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
120. It is noted that fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measure would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

N. CONCLUSION

121. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made and facts available before the Authority as recorded in the above findings and on the basis of the above analysis of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, the Authority concludes that:
 - a. There is continued dumping of the subject goods from subject countries except for China. Except China, imports are likely to enter the Indian market at dumped prices in the event of expiry of duty.
 - b. The domestic industry has suffered continued injury.
 - c. The information on record shows likelihood of continuation of dumping and injury in case the anti-dumping duty in force is allowed to cease.
 - d. Factors such as positive price undercutting, excess capacities over demand and significant volume of exports to third country at price below normal value and Non-Injurious Price collectively establish likelihood of dumping and injury to the domestic industry in case the ADD in force on imports from Thailand, Malaysia and Sri Lanka is allowed to cease.

O. RECOMMENDATIONS

122. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and the causal link.
123. Having concluded that there is likelihood of continuation of dumping and injury if the existing anti-dumping duties are allowed to cease, the Authority is of the view that continuation of duty is required on the import of PUC from the subject countries except China PR. The Authority examined the quantum of duty that should be recommended. The Authority considered the volume of dumped and injurious exports from cooperating exporters to India and to the rest of the world. The Authority considers it appropriate to recommend continuation of existing quantum of ADD in respect of all exporters/

producers, except Robin Resources. In case of Robin Resources, however, it would be appropriate to modify the quantum of ADD, considering the dumping margin and injury margin found in the present investigation. Further, the non-cooperating producers and exporters in this sunset review investigation are required to be accorded residual duty, as applicable at present, as per the consistent practice of not rewarding non-cooperation. Accordingly, the anti-dumping duties for responding producers and non-cooperative producers from subject countries are recommended as per the duty table below. The Authority, thus, considers it necessary to recommend continuation of definitive anti-dumping duty as modified, on all imports of the subject goods mentioned in column 3 from Malaysia, Thailand and Sri Lanka as per column 7 in the duty table below, for a further period of five years.

Duty Table

SN	Heading	Description	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	4411	Plain Medium Density Fibre Board from 6MM and above	Thailand	Any country including Thailand	Panel Plus MDF Company Limited	45.27	Cubic Meters	USD
2.	- do -	- do -	Thailand	Any country including Thailand	Any producer other than S.No. 1 above	45.27	Cubic Meters	USD
3.	- do -	- do -	Any country other than Thailand	Thailand	Any	45.27	Cubic Meters	USD
4.	- do -	- do -	Malaysia	Any country including Malaysia	Robin Resources (Malaysia) Sdn. Bhd.	13.29	Cubic Meters	USD
5.	- do -	- do -	Malaysia	Any country including Malaysia	Any producer other than S.No. 5 above	36.10	Cubic Meters	USD
6.	- do -	- do -	Any country other than Malaysia	Malaysia	Any	36.10	Cubic Meters	USD
7.	- do -	- do -	Sri Lanka	Any country including Sri Lanka	Any	26.49	Cubic Meters	USD
8.	- do -	- do -	Any country other than Sri Lanka	Sri Lanka	Any	26.49	Cubic Meters	USD

P. FURTHER PROCEDURE

124. An appeal against the order of the Central Government arising out of these findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the with the relevant provisions of the Act.

B. B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority